● वर्ष-4
● अंक-131
रायपुर, शनिवार
11 जनवरी 2025
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» हेल्दी डाइट के लिए खाइए ब्राउन राइस

मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रमः केंद्रीय कृषि मंत्री ने की 3 लाख से अधिक नए आवासों की घोषणा

डबल इंजन की सरकार बदल रही प्रदेश की तस्वीर-शिवराज

रायपुर। केन्द्रीय कृषि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राज्य में विष्णु देव साय की डबल इंजन सरकार प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य कर रही है। वे आज दुर्ग जिले के नगपुरा में आयोजित मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के पैर पखार कर उनका अभिनंदन किया। केन्द्रीय मंत्री चौहान ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 लाख 3 हजार 384 नए आवासों की घोषणा की।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को आवास का वादा किया था, जो आज साकार हो रहा है। उन्होंने बताया कि देशभर में गरीबों को पक्के घर देने के इस ऐतिहासिक प्रयास के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में अब तक 8 लाख 47 हजार मकान पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को और अधिक समावेशी बनाने के लिए नई पात्रता मानदंड निर्धारित किया गया है, जिनमें अब अधिकतम आय सीमा बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा जिनके पास ढाई एकड़ सिंचित भूमि या पांच एकड़ असिंचित भूमि है, वे भी अब इस योजना के तहत पात्र होंगे। हितग्राही अब स्वयं भी अपने आवास हेतु आवेदन और सर्वेक्षण कर सकते हैं।

केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेती-किसानी को बढ़ावा देने की दिशा में अद्भूत काम हो रहे हैं। फसलों का उत्पादन बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और फसल विविधिकरण पर जोर दिया जा रहा है। धान की नई-नई किस्में भी जारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान आ रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सम्बोधित करते हुए कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना आरंभ की

थी। छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार आई। डबल इंजन की सरकार बनी। हमने शपथ लेने के अगले ही दिन कैबिनेट की बैठक की और 18 लाख आवास स्वीकृत कर दिये। आज इस निर्णय से छत्तीसगढ़ के लाखों हितग्राहियों के चेहरे में संतोष नजर आता है। उन्होंने जो मकान का सपना देखा था, वो अब पूरा हो रहा है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमने अपनी सरकार का एक साल पूरा कर लिया है और जनता के समक्ष एक साल का रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत किया है। हमारी परीक्षा की घड़ी शपथ ग्रहण के बाद ही शुरू हुई थी और सबसे पहला वायदा कैबिनेट की बैठक में हमने पूरा कर दिया। इससे हम लोग आश्वस्त हो गये और एक साल के भीतर ही मोदी जी की गारंटी के सभी प्रमुख वायदे हमने पूरे कर दिये हैं। शपथ के दो सप्ताह के भीतर हमने श्रद्धेय अटल जी की जयंती सुशासन दिवस के अवसर पर 13 लाख किसान भाइयों को 2 साल के बकाया धान की बोनस राशि अंतरित की। हमने वायदे के अनुरूप 3100 रुपए प्रति क्विंटल और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान भी खरीदा। हमने पिछली बार 145 लाख मीट्रिक टन रिकार्ड धान की खरीदी की । पिछली बार किसानों के खाते में हमने कुल 49 हजार करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। यह छत्तीसगढ़ के कृषि इतिहास में एक रिकार्ड की तरह दर्ज हो गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लगातार इस बात की मानिटरिंग कर रहे हैं कि तेजी से पीएम आवासों पर काम हो सके। गृह पोर्टल के माध्यम से जीआईएस मैपिंग और सटीक योजना तैयार की जा रही है। हमने पीएम आवास के लिए निर्माण सामग्री की आपूर्ति का जिम्मा लखपति दीदी कार्यक्रम के अंतर्गत स्वसहायता समूहों को सौंपा है। इससे महिला सशक्तिकरण में भी बड़ी मदद मिल रही है, इस काम में आवास मित्र प्रभावी रूप से हितग्राहियों की मदद कर रहे हैं जिसके चलते आवास निर्माण समय पर पूरा हो रहा है। हितग्राहियों को कम लागत पर निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने हमने छूट कूपन की व्यवस्था की है। शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए टोलफ्री नंबर की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पित माओवादियों तथा नक्सल प्रभावित परिवारों के लिए 15 हजार आवास बनाने का निर्णय लिया गया है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए लाई गई पीएम जनमन योजना का क्रियान्वयन भी प्रदेश में तेजी से हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए 8 लाख 47 हजार नए मकानों की मंजूरी देकर प्रदेश के आवासहीन लोगों के प्रति अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए छत्तीसगढ़ में 18 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सामंजस्य से प्रदेश में आवास और सड़क निर्माण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। पीएम जनमन योजना के तहत 32 हजार आवासों की स्वीकृति दी गई है और राज्य के हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2449 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं के तहत छत्तीसगढ़ में ग्रामीण संपर्क को मजबूत किया जा रहा है।

कार्यक्रम में रूरल मेसन प्रशिक्षणार्थियों को सामग्री का वितरण किया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और स्वयंसेवी संस्थाओं को सम्मानित किया गया। व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि और स्वच्छता किट वितरित की गई। ड्रोन दीदियों और लखपति दीदियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनके कार्यों की सराहना की गई। स्वामित्व योजना के तहत हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख वितरित किए गए। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव, वन मंत्री केदार कश्यप, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल,सहित अनेक जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

निखिल कामथ के पॉडकास्ट पर पीएम मोदी ने दिया जवाब

बिना पैसों के राजनीति संभव नहीं?

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ज़ेरोधा के सह-संस्थापक निखिल कामथ के साथ अपने पहले पॉडकास्ट में विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से बात की। दो घंटे तक चली बातचीत के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या राजनीति में पैसा एक अनिवार्य हिस्सा है? अगर देश का युवा राजनीति में आना चाहता है, तो वे कहते हैं कि इसके लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है जो हमारे पास नहीं है। स्टार्टअप उद्योग में, जब हमारे पास

कोई विचार होता है, तो हम अपने दोस्तों और परिवार से पैसे लेते हैं। इसे बीज चक्र कहते हैं। कामथ ने पूछा राजनीति में यह कैसे होगा।

जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए लोगों से एक-एक रुपये का चंदा लिया। एक सार्वजनिक बैठक में उन्होंने हिसाब दिया कि उन्हें कितना पैसा मिला। मुझे लगता है कि उन्होंने केवल ?250 ही खर्च किए। उन्होंने बहुत ही कम अंतर से जीत हासिल की। यह सत्य नहीं है कि समाज सत्य को स्वीकार नहीं करता। आपमें धैर्य और समर्पण होना चाहिए. आपका %कॉन्ट्रैक्ट% वाला भाव नहीं होना चाहिए, मतलब कि आप केवल वोट के लिए कुछ करें। इस तरह के रवैये से आप सफल नहीं हो सकते।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल प्रतिनिधि चुनने की राजनीतिक मानसिकता से ऊपर उठने का आह्वान किया। हमें सांसद या विधायक चुनने तक सीमित इस राजनीति से बाहर आने की जरूरत है। अगर हम समाज से जुड़े किसी भी काम से जुड़े हैं तो इसका राजनीतिक प्रभाव ज्यादा पड़ता है। अगर कोई छोटा सा आश्रम चलाता है और लड़कियों को पढ़ाता है।

पीएम मोदी प्रयागराज में कुंभ का आमंत्रण

नईदिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी को प्रयागराज में कुंभ मेले के लिए आमंत्रित करने के लिए शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे हैं। बैठक शाम 5 बजे निर्धारित है. महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला है, जिसमें इस साल 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को महाकुंभ 2025 से संबंधित जानकारी प्रसारित करने के लिए समर्पित एक एफएम चैनल कुंभवाणी का उद्घाटन किया।

प्रमुख समाचार

सुखबीर बादल का इस्तीफा मंजूर, वर्किंग कमेटी का फैसला

नईदिल्ली। शिअद प्रवक्ता दलजीत सिंह चीमा ने शुक्रवार को कार्यसमिति की बैठक के बाद फैसले की पुष्टि की. बादल के इस्तीफे की स्वीकृति पार्टी के भीतर आंतरिक बहस के बाद हुई, जहां नेतृत्व ने शुरू में पार्टी के धर्मनिरपेक्ष संविधान और राजनीतिक पंजीकरण के साथ अकाल तख्त के

निर्देशों के टकराव के बारे में चिंता व्यक्त की थी। हालाँकि, संगठनात्मक परिवर्तन के लिए धार्मिक निकाय के आह्वान के कारण अंततः इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। शिरोमणि अकाली दल की कार्य समिति ने अकाल तख्त के निर्देश के बाद पार्टी अध्यक्ष पद से सुखबीर सिंह बादल का इस्तीफा आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। शिअद प्रवक्ता दलजीत सिंह चीमा ने शुक्रवार को कार्यसमिति की बैठक के बाद फैसले की पुष्टि की. बादल के इस्तीफे की स्वीकृति पार्टी के भीतर आंतरिक बहस के बाद हुई, जहां नेतृत्व ने शुरू में पार्टी के धर्मनिरपेक्ष संविधान और राजनीतिक पंजीकरण के साथ अकाल तख्त के निर्देशों के टकराव के बारे में चिंता व्यक्त की थी। हालाँकि, संगठनात्मक परिवर्तन के लिए धार्मिक निकाय के आह्वान के कारण अंततः इस्तीफा स्वीकार कर लिया

विकास पर प्रधानमंत्री जी का पीआर हावी है: प्रियंका गांधी

नईदिल्ली। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रचार पर ध्यान केंद्रित करने का आरोप लगाया और दावा किया कि प्रधान मंत्री के जनसंपर्क (पीआर) पर पर्याप्त धन खर्च किया गया है, जबकि सरकार छात्रवृत्ति प्रदान करने में विफल

रही जो कई युवाओं के जीवन को बदल सकती थी। उन्होंने राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (एनटीएसई) छात्रवृत्ति के निलंबन पर चिंता जताई, जो परंपरागत रूप से प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल करने और देश के विकास में योगदान करने में मदद करती थी।एक समाचार रिपोर्ट का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि 1963 में शुरू किए गए छात्रवृत्ति कार्यक्रम ने देश भर में कई बच्चों के लिए अवसर प्रदान किए, लेकिन पिछले तीन वर्षों से इसे रोक दिया गया है, जिससे इच्छुक छात्रों के लिए अवसर खो गए हैं। प्रियंका गांधी ने सरकार पर युवा छात्रों के कल्याण पर प्रधान मंत्री के व्यक्तिगत प्रचार को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया और बताया कि इस अवधि के दौरान प्रधान मंत्री के लिए जनसंपर्क पर 62 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

राहुल गांधी को पुणे कोर्ट से मिली जमानत

नईदिल्ली। पुणे की एक अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में जमानत दे दी है। यह मामला गांधी द्वारा की गई उस टिप्पणी से संबंधित है जिसमें कथित तौर पर कुछ व्यक्तियों को बदनाम किया गया था। भाषण में, गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि

वीडी सावरकर ने एक किताब में एक घटना के बारे में लिखा था जहां उन्होंने और कुछ दोस्तों ने एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी, सावरकर कथित तौर पर इसके बारे में खुश महसूस कर रहे थे सात्यकी सावरकर ने इन आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया और उन्हें काल्पनिक, झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताया। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई थी, और वीडी सावरकर ने इस आशय पर कभी कुछ नहीं लिखा था। अपनी शिकायत में सावरकर ने कहा कि गांधी के बयान उनके परपोते की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शिकायत के बाद पुणे कोर्ट ने पुलिस को मामले की जांच करने का निर्देश दिया। विश्रामबाग पुलिस स्टेशन ने जांच की और निष्कर्ष निकाला कि मानहानि के आरोपों का समर्थन करने वाले प्रथम दृष्टया सबूत थे।

वक्फ बोर्ड भू-माफियाओं का बोर्ड, योगी की दो टूक

नईदिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार वक्फ के नाम पर ली गई एक-एक इंच जमीन वापस हासिल करेगी। एक निजी समाचार चैनल द्वारा आयोजित महाकुंभ महासम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने दावा किया कि सनातन धर्म की विश्वास प्रणाली दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, जो किसी भी धर्म या संप्रदाय की तुलना में ऊपर है। इसके साथ ही उन्होंने वक्फ बोर्ड पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, यह कहना मुश्किल है कि यह वक्फ बोर्ड है या भू-माफियाओं का बोर्ड है।योगी ने कहा कि यह वक्फ बोर्ड है या भू-माफियाओं का बोर्ड है। एक-एक इंच लैंड वापस लेंगे। उन्होंने कहा कि हम वक्फ के नाम पर ली गई एक-एक इंच जमीन वापस हासिल करेंगे और इसका इस्तेमाल गरीबों के लिए आवास, शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल बनाने में किया जाएगा। उन्होंने कहा, सनातन धर्म का कद आकाश से भी ऊंचा है और इसकी गहराई समुद्र से भी अधिक गहरी है। इसकी तुलना किसी भी संप्रदाय या धर्म से नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं की कड़ी आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वे डॉ. राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों को कायम रखने में विफल रहे।

सक्रिय राजनीति में रघुबर दास की वापसी, बीजेपी में शामिल

नईदिल्ली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी में फिर से शामिल हो गए। दोबारा सक्रिय राजनीति में लौटने के बाद उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि पार्टी झारखंड में सत्ता में वापसी करेगी। विधानसभा चुनावों में पार्टी

की हार के बाद सक्रिय राजनीति में फिर से प्रवेश करने के लिए उन्होंने 24 दिसंबर को ओडिशा के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था, जहां वह राज्य में जेएनएम के नेतृत्व वाले गठबंधन को सत्ता से हटाने में असमर्थ रही। भाजपा के राज्य मुख्यालय में पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष रवींद्र राय, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ और सैकड़ों समर्थकों की मौजूदगी में दास का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर दास ने कहा कि वह 1980 के बाद दूसरी बार पार्टी की सदस्यता लेकर खुश हैं और वह लोगों की सेवा करेंगे। 2023 में ओडिशा के राज्यपाल का पद संभालने के बाद उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। 2024 के विधानसभा चुनावों में, राज्य अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक, पार्टी के सभी सदस्यों ने अपना ईमानदार प्रयास किया।

विकसित भारत की यात्रा में एनआरआई, दुनिया में बने भारत के ब्रांड एंबेसडर

शिव शुक्ला

सितंबर 2014 में मैडिसन स्क्वायर में 'भारत माता की जय' के नारे गूंजे। न्यूयॉर्क शहर में हजारों लोगों द्वारा इस नारे को बुलंद करना एक अभूतपूर्व क्षण था। इसने?प्रवासी समुदाय से भारत के जुड़ाव में नए युग का सूत्रपात किया। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दुनिया ने विभिन्न देशों में भारतीय प्रवासियों की शानदार सभाओं को देखा। वह?शायद पहले वैश्विक नेता हैं, जिन्होंने अपने देश के प्रवासियों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर इतना?महत्व दिया है। अमेरिका में 'हाउडी मोदी' से लेकर कुवैत में हाल ही में हुए 'हाला मोदी' जैसे कार्यक्रमों ने, भारतीय प्रवासियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के दीर्घकालिक व्यक्तिगत जुड़ाव के कारण वैश्विक स्तर पर प्रमुखता हासिल की।

ओडिशा इस साल प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी कर रहा है। बीते कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल इस आयोजन में भारतीय प्रवासियों की भागीदारी को बढ़ाया है, बल्कि लाखों एनआरआई के बीच उनके गौरव और उद्देश्य की भावना को भी बढ़ाया है। प्रशासनिक भूमिकाओं में मोदी का प्रवेश गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में हुआ, लेकिन प्रवासी समुदाय व दुनिया के साथ उनका संबंध युवा प्रचारक के रूप में उनके शुरुआती वर्षों से है। उन्होंने 1980 के दशक की शुरुआत में भारत से बाहर यात्रा की। आरएसएस में उनके पूर्व सहयोगी याद करते हैं कि मोदी नियमित रूप से अन्य देशों के मित्रों से मिलते थे। जापान के नागोया से एक दोस्त ने उन्हें नाइकी के जूते भेजे थे, जबकि उन्होंने बदले में श्रीमद्भागवत गीता की प्रतियां भेजीं।?वह गुजरात में विश्व संघ शिविर जैसे प्रवासी कार्यक्रमों के प्रमुख आयोजक भी थे।

स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक शिकागो संबोधन के 100वें वर्षगांठ समारोह में भाग लेने के लिए मोदी?1993 में अमेरिका गए, जहां उन्होंने 'ग्लोबल विजन 2000' सम्मेलन में भाषण दिया। कई भारतीय परिवार 1997 में मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान उन्हें दी गई मेजबानी को याद करते हैं। नरेंद्र मोदी का प्रवासी समुदाय से संबंध अमेरिका और यूरोप से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वर्ष 2000 में विश्व हिंदू सम्मेलन के लिए त्रिनिदाद?व टोबैगो की यात्रा के दौरान मोदी गुयाना भी गए।?'मिनी इंडिया' कहे जाने वाले मॉरीशस ने 1998 में रामायण सम्मेलन

की मेजबानी की, जहां मोदी ने भगवान राम और मॉरीशस के साथ भारत के संबंधों पर भाषण दिया। उन्होंने उन्हें कम से कम पांच दोस्तों को भारत आने और देश के पर्यटन में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। इस सिलसिले में वह अक्सर 'चलो इंडिया' नारे का इस्तेमाल करते थे।

गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी ने गुजरात को वैश्विक निवेश के मानचित्र पर लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव व प्रवासी संबंधों का लाभ उठाया। उन्होंने जापान, चीन, रूस, यूरोपीय देशों और अमेरिका जैसे कई देशों के साथ संबंध विकसित किए। 2001 के भूकंप के बाद जापान के ह्योगो प्रांत ने गुजरात के पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभाई। मोदी के नेतृत्व में, गुजरात ने लंदन, ज्यूरिख, जिनेवा और अन्य वैश्विक शहरों में वाइब्रेंट गुजरात रोड शो की मेजबानी की, जिससे वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलनों के लिए भागीदारी और निवेश आकर्षित हुआ। जब गांधीनगर में महात्मा मंदिर का निर्माण किया जा रहा था, तब उन्होंने दुनिया भर के गुजराती प्रवासियों से अपने क्षेत्रों से मिट्टी भेजने की अपील की और इस उद्देश्य के लिए कई देशों में कलश भेजे।

अपने अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव और वैश्विक प्रवासी संबंधों के माध्यम से नरेंद्र मोदी ने स्थायी संबंध बनाए, जिससे गुजरात को आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ने में मदद मिली। बाद में, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने प्रवासी समुदाय की क्षमता का और भी अधिक उपयोग किया। प्रधानमंत्री के रूप में प्रवासी भारतीयों से उनका संपर्क अमेरिका के ऐतिहासिक मैडिसन स्क्वायर गार्डन कार्यक्रम से शुरू हुआ और ह्यूस्टन में 'हाउडी मोदी' तथा 2024 में न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में 'मोदी एंड यूएस' जैसे कार्यक्रमों के साथ जारी रहा। लंदन में वेंबली स्टेडियम की सभा, यूएई में अहलान मोदी, तेल अवीव में हुए कार्यक्रम जैसे कई अन्य ऐतिहासिक आयोजन हुए। हजारों लोगों की उपस्थिति में सिडनी में हुए ऐतिहासिक प्रवासी कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने प्रधानमंत्री को 'मोदी बॉस हैं' की संज्ञा दी।

भारत ने ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन संकट मोचन, ऑपरेशन राहत और वंदे भारत मिशन जैसे कई बचाव अभियानों के माध्यम से प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। इन प्रयासों ने वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव को भी उजागर किया। प्रधानमंत्री मोदी एनआरआई को 'भारत का ब्रांड एंबेसडर' कहते हैं और?विकसित भारत की यात्रा में उनकी भूमिका?को अहम?बताते?हैं। वैश्विक?भारतीय समुदाय के साथ उनका दशकों पुराना जुड़ाव निस्संदेह इस मिशन में खासा योगदान देगा।

बीजापुर ब्लास्ट जैसी वारदात सुकमा में दोहराने की नक्सली साजिश

■ 10 किलो का आईईडी बरामद

सुकमा। बस्तर संभाग के सुकमा जिले में सुरक्षाबल के जवानों को नक्सली मोर्चे पर आज एक बड़ी सफलता मिली है। सुकमा की जमीन पर जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए दफन किये गए मौत के सामान को जवानों ने बरामद करके मौके पर ही नष्ट कर दिया है। जिसका वीडियो भी सामने आया है। ब्लास्टिंग का वीडियो काफी भयावह है।

सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि कोंटा और गोलापल्ली के बीच सड़क निर्माण का काम जारी है। जिसकी सुरक्षा पर सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। स्थानीय पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवानों लगातार सड़क की डीमाइनिंग कर रहे हैं। डीमाइनिंग के दौरान कोंटा और गोलापल्ली के बीच बेलपोच्चा के पास जवानों ने आईईडी बरामद किया। आईईडी 10 किलो का है, जिसे नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए 2 दिन पहले प्लांट किया था।

सुकमा में सुरक्षाबल की सतर्कता से बड़ी नक्सली घटना को टाला गया। बरामद किए गए आईईडी बम को सुरक्षित तरीके से सूझबूझ के साथ मौके पर ही नष्ट कर दिया। एसपी ने बताया कि इलाके में लगातार जवान सर्चिंग और डीमाइनिंग की कार्रवाई कर रहे हैं।

सुरक्षाबल के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बस्तर में 4 दशकों से काबिज माओवादी हमेशा से ही आईईडी बम का इस्तेमाल करते आए हैं। इन बमों से सुरक्षाबल के जवानों को काफी नुकसान भी हुआ है। इसके अलावा स्थानीय आदिवासी ग्रामीणों के साथ ही मवेशियों को भी बम से नुकसान होता आया है। बीते सालों में दंतेवाड़ा जिले के अरणपुर में भी माओवादियों ने आईडी ब्लास्ट किया था। जिसमें कई जवान शहीद हो गए थे।

सुकमा में मारे गए तीन नक्सलियों पर कुल 18 लाख का था इनाम

सुकमा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में हुई मुठभेड़ में तीन नक्सली मारे गए थे। ये तीनों नक्सली वरिष्ठ सदस्य थे और उन पर कुल 18 लाख रुपये का इनाम था। सुकमा के पालीगुड़ा-गुंडराजगुडेम की पहाड़ी पर गुरुवार सुबह सुरक्षाकर्मियों की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी, तभी मुठभेड़ हो गई। घटनास्थल से तीन नक्सलियों के शव बरामद किये गये।

एक अधिकारी ने बताया कि मारे गए नक्सलियों में से एक कोरसा महेश इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) का विशेषज्ञ था और 2023 और 2024 में बेदरे (बीजापुर) और जगरगुंडा (सुकमा) इलाकों में हुई हिंसक घटनाओं का कथित मास्टरमाइंड था। महेश माओवादियों के प्लाटून नंबर के डिप्टी कमांडर के रूप में सक्रिय था। सुकमा के पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने कहा कि 30 और उस पर आठ लाख रुपये का इनाम था। उन्होंने कहा कि दो अन्य, मदवी नवीन और अवलम भीमा, क्षेत्र समिति के सदस्य थे और उन पर पांच लाख रुपये का इनाम था।

अधिकारी ने कहा कि मुठभेड़ स्थल से दो बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (बीजीएल), एक 12 बोर राइफल, तीन टिफिन बम, पांच बीजीएल गोले और भारी मात्रा में विस्फोटक और माओवादी से संबंधित सामान बरामद किए गए।

महेश आईईडी बनाने, लगाने और चलाने में विशेषज्ञ था। वह कथित तौर पर कई घटनाओं में शामिल था। दिसंबर, 2023 में बेद्रे के पास नक्सली हमला, जिसमें सीआरपीएफ उप-निरीक्षक सुधाकर रेड्डी की मौत हो गई थी और एक ट्रक पर आईईडी विस्फोट में शामिल था। चव्हाण ने कहा कि पिछले साल जून में जगरगुंडा में सीआरपीएफ के दो जवानों की मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक, इस साल अब तक राज्य में अलग-अलग जगहों पर हुई तीन मुठभेड़ों में नौ नक्सली मारे गए हैं।

एक लाख के इनामी नक्सली दिवास ने किया सरेंडर, आमदई एलओएस पार्टी का था सदस्य

कोंडागांव। कोंडागांव जिले में एक लाख के इनामी नक्सली दिवास उर्फ गनपत मंडावी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। वह माओवादी संगठन के आमदई एलओएस पार्टी का सदस्य था और 2009 से 2024 तक विभिन्न भूमिकाओं में सक्रिय रहा। छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति और सुरक्षाबलों के लगातार दबाव से प्रभावित होकर दिवास ने आत्मसमर्पण का निर्णय लिया।

नक्सलियों की खोखली विचारधारा और शोषण से तंग आकर उसने मुख्यधारा में जुड़ने का संकल्प लिया।

दिवास कई बड़े नक्सली हमलों में शामिल रहा, जिनमें 2012 में बस्तर के ककनार चौकी पर फायरिंग, 2015 और 2017 में पुलिस पार्टी पर फायरिंग, 2018 में ईरपानार फायरिंग (चार जवान शहीद) 2024 में थुलथुली मुठभेड़ (36 नक्सली मारे गए) इन घटना में शामिल रहा। आत्मसमर्पण के बाद दिवास को तत्काल प्रोत्साहन राशि 25 हजार रुपये दी गई। पुनर्वास नीति के तहत अन्य लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया जारी है।

आत्मसमर्पण की इस सफलता में बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी, कोंडागांव एसपी वॉय अक्षय कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की कुशल रणनीति शामिल है। सुरक्षा बल लगातार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सिविक एक्शन कार्यक्रम चला रहे हैं। यह आत्मसमर्पण नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक और सफलता है और समाज को शांति की ओर ले जाने में सहायक सिद्ध होगा।

जिला पंचायत की नौ सीटें महिला आरक्षित ओबीसी को मिली केवल एक सीट

बालोद। बालोद जिले के पंचायती राज के अंतर्गत जिला पंचायत की 14 सीटों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न की गई। इसके तहत 14 में से नौ सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हुईं। वहीं, कई नेताओं के चेहरे पर मायूसी देखने को मिली। वहीं, कुछ नेताओं ने अपनी पत्नी को मैदान में उतारने की बात कही। कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत अध्यक्ष सोना देवी देशलहरा ने कहा कि यहां पर आरक्षण में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है, ये सरकार का बेहतरीन कदम है। उन्होंने कहा कि दोबारा जिला पंचायत के अध्यक्ष पर जरूर महिला काबिज होगी।

डिप्टी डायरेक्टर पंचायत आकाश सोनी ने आरक्षण के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि जिला पंचायत की 14 सीटों के लिए आरक्षण किया गया। वहीं, 101 जनपद सदस्यों के आरक्षण के लिए प्रक्रिया संपन्न की जा चुकी है। वहीं, जनपद पंचायत अध्यक्ष के पांच पदों के लिए आरक्षण संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि जनपद स्तर पर सभी सरपंच पदों के लिए आरक्षण किया जा रहा है। वहीं, शासन स्तर पर जिला पंचायत आरक्षण के लिए कल प्रक्रिया की जाएगी।

बालोद जिले के जिला पंचायत की बात करें तो जो पंचायती राज के दिग्गज माने जाते हैं, उनकी सभी सीट महिला आरक्षित हो गई हैं। वहीं, ओबीसी वर्ग को केवल एक ही सीट मिल पाई है, जिसके कारण ओबीसी वर्ग में नाराजगी देखने को मिल रही है। यहां तक कि कई ऐसी जगह हैं, जहां पर आरक्षण

के कारण नेताओं के चेहरे उतरे हुए हैं।

जनपद पंचायत आरक्षण की स्थिति

बालोद - अनुसूचित जनजाति महिला, गुरूर - अनारक्षित महिला, गुण्डरदेही - अनारक्षित मुक्त, डौंडीलोहारा - अनारक्षित महिला, डौंडी - अनुसूचित जनजाति मुक्त।

जिला पंचायत बालोद आरक्षण सूची

क्षेत्र क्रमांक 1- अनुसूचित जाति महिला, क्षेत्र क्रमांक 2- अनारक्षित महिला, क्षेत्र क्रमांक 3- अनारक्षित महिला, क्षेत्र क्रमांक 4- अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, क्षेत्र क्रमांक 5- अनारक्षित, क्षेत्र क्रमांक 6- अनुसूचित जनजाति महिला, क्षेत्र क्रमांक 7- अनुसूचित जनजाति महिला, क्षेत्र क्रमांक 8- अनुसूचित जनजाति, क्षेत्र क्रमांक 9- अनारक्षित महिला, क्षेत्र क्रमांक 10- अनारक्षित, क्षेत्र क्रमांक 11- अनुसूचित जनजाति महिला, क्षेत्र क्रमांक 12- अनुसूचित जनजाति, क्षेत्र क्रमांक 13- अनारक्षित महिला, क्षेत्र क्रमांक 14- अनारक्षित।

12 साल से बन रहे बाईपास के पूरा होने का जनता कर रही इंतजार

खैरागढ़। शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 12 साल पहले बाईपास का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन आज तक वह अधूरा है। बाईपास पूरा न होने की वजह से भारी वाहन अभी भी शहर के बीच से ही गुजर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब खैरागढ़ की जनता जल्द से जल्द बाईपास को पूर्ण करने की मांग कर रही है। खैरागढ़ शहर में सड़क हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिला बनने के बाद से यहां यातायात का दबाव भी तेजी से बढ़ा है। बड़े वाहनों का शहर के बीच से गुजरना इसका मुख्य कारण है। इस मार्ग पर कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ प्रसिद्ध संगीत विश्वविद्यालय भी स्थित है। ऐसे में बड़े वाहनों के गुजरने से न केवल यातायात व्यवस्था चरमराई हुई है, बल्कि लगातार दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। डोंगरगढ़, कवर्धा, बिलासपुर, राजनांदगांव समेत मध्यप्रदेश तक जाने वाले बड़े वाहन खैरागढ़ के मुख्य मार्ग से होकर गुजरते हैं। इस कारण न केवल सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं, बल्कि यातायात व्यवस्था भी पूरी तरह बाधित हो जाती है। शहर के बीचों-बीच कलेक्ट्रेट, एसपी कार्यालय और संगीत विश्वविद्यालय जैसे प्रमुख स्थल मौजूद हैं, जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इन स्थानों के आस-पास बड़े वाहनों के आवागमन के चलते यातायात जाम और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है।

आरोप-प्रत्यारोप में उलझे राजनीतिक दल

12 साल पहले शुरू हुआ बाईपास निर्माण आज तक अधूरा पड़ा है। राजनीतिक पार्टियां आरोप-प्रत्यारोप में उलझी हुई हैं, लेकिन इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। सड़क हादसों में कई लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया है। बाईपास पूरा न होने की वजह से शहरवासियों का सब्र टूट रहा है। अब देखना यह होगा कि शासन-प्रशासन इस मुद्दे पर कब जागता है।

गन्ना किसानों का 50 करोड़ रुपये लंबित

दो माह बाद भी चीनी मिल ने नहीं किया भुगतान, प्रदर्शन की तैयारी

कबीरधाम। कबीरधाम जिला गन्ना व गुड़ की मिठास के लिए जाना जाता रहा है। यहां के किसान गन्ने की खेती कर अपना जीवन यापन करते हैं। यहां गन्ने का उत्पादन इतना है कि दो सहकारी शक्कर कारखाना के साथ लगभग 300 निजी गुड़ फैक्टरी संचालित हो रही हैं, लेकिन सहकारी शक्कर कारखाना में किसानों को गन्ना बेचने के दो माह बाद भी अपनी उपज के दाम नहीं मिले हैं।

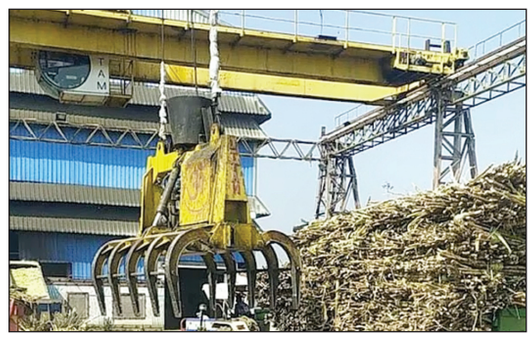

दरअसल, जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना में गन्ना खरीदी करने के बाद किसानों को रुपये नहीं मिले हैं। ऐसे में किसानों को आर्थिक रूप से परेशानी हो रही है। इसे लेकर आने वाले दिनों में कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन की तैयारी है। कांग्रेस नेता रवि चंद्रवंशी ने बताया कि इस कारखाना में बीते पेराई सीजन का लाभांश राशि 20 करोड़ और इस सत्र का मूल भुगतान 30 करोड़, कुल 50 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है।

उन्होंने बताया कि दूसरी ओर कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना ने अब तक अपने किसानों को करीब 19 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। शासन प्रशासन को एक हफ्ते के भीतर किसानों को राशि देने की मांग की है। राशि नहीं मिलने की स्थिति में किसानों के साथ मिलकर अनिश्चितकालीन चक्काजाम करने की चेतावनी दी है।

लौह पुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित कबीरधाम जिले के पंडरिया ब्लॉक के ग्राम विशेषरा में स्थापित है। यह शक्कर कारखाना राज्य के चौथे क्रम का शक्कर कारखाना है, जो कि सत्र 2016-17 में निर्माण होकर 21 जनवरी 2017 से प्रारंभ हुआ है। कारखाना की पेराई क्षमता 2500 टीसीडी है। साथ ही कारखाना में 14 मेगावाट सह-उत्पादन का पावर प्लांट स्थापित है।

इस कारखाना के कार्यक्षेत्र अतंर्गत कबीरधाम जिले का पंडरिया ब्लॉक, मुंगेली जिले के मुंगेली, लोरमी व पथरिया ब्लॉक, बिलासपुर जिले का तखतपुर ब्लॉक आता है। कारखाना में 11881 किसान शेयरधारी सदस्य है,जो कारखाना में गन्ना आपूर्ति कर लाभान्वित हो रहे है। पेराई सत्र 2021-22 में 13.12 प्रतिशत रिकव्हरी के साथ कारखाना पूरे भारत देश में प्रथम स्थान पर रहा है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

सक्ती में पार्षदों ने ठेकेदारों के खिलाफ खोला मोर्चा

सक्ती। छत्तीसगढ़ के सक्ती में निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर भाजपा के कुछ पार्षद और नेता नगर पालिका के अधिकारियों को लेकर वार्ड नंबर 17 पहुंचे। वहां मौके पर चल रहे नाली निर्माण कार्य को देख नाराज पार्षदों और नेताओं ने ठेकेदार और नगर पालिका के अधिकारियों को खरी खोटी सुनाना चालू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष धनंजय नामदेव का कहना है कि ठेकेदार की बार बार शिकायत आ रही है। इसके द्वारा सभी जगह ऐसे ही गुणवत्ताहीन कार्य कराया जा रहा है। इसके सभी कार्यों का भौतिक सत्यापन और क्वालिटी टेस्ट फिर से पीडब्लूयडी विभाग से कराएंगे। अगर रिपोर्ट फेल हुई तो ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने की मांग करेंगे। इसमें जो भी जिम्मेदार हैं, सभी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। धनंजय नामदेव ने कहा वार्ड नंबर 17 में नगर पालिका नाली बनवा रही है लेकिन वह पूरी तरह से गुणवत्ताहीन बनी है। उसे फिर से तोड़कर बनाना चाहिए। वहीं नगर पालिका सक्ती के इंजीनियर तारकेश्वर नायक का कहना है कि पार्षदों की शिकायत पर मौके पर पहुंचकर जांच की गई है।

आमापारा पार्षद से मारपीट करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

कांकेर। कांकेर नगर के आमापारा पार्षद से मारपीट करने वाले दो आरोपियों को कांकेर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुरुवार रात दो अज्ञात आरोपियों ने नगर के आमापारा के पार्षद सतीश दीपक के साथ मारपीट की थी। पार्षद ने पूरे मामले की रिपोर्ट नगर कोतवाली में दर्ज कराई थी। थाना प्रभारी मनीष नागर ने बताया कि घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी जिला बदर एवं आदतन गुंडा, बदमाश हैं। आरोपी आशीष सारथी को रामनगर पहाड़ी से घेराबंदी कर हिरासत में लिया गया, जिससे कड़ाई से पूछताछ करने पर धारदार चुड़ा और लूट का मोबाइल जब्त किया गया है। आरोपी आशीष सारथी उर्फ जग्गा निवासी श्रीरामनगर कांकेर और सूरज उर्फ आदि देहारी निवासी राजापारा कांकेर को गिरफ्तार किया गया है। बीती रात पार्षद का रास्ता रोककर आरोपियों ने मारपीट की थी और घटनास्थल से फरार हो गए थे। पूरे मामले को लेकर नगर के पार्षदों में काफी आक्रोश था।

क्रिकेट कमेंटेटर किडनी की गंभीर बीमारी से ग्रसित

बलरामपुर रामानुजगंज। सनवाल थाना क्षेत्र के सुप्रसिद्ध एवं लोकप्रिय क्रिकेट कमेंटेटर मोहम्मद सलाम आजाद किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इलाज में काफी खर्च हो रहा है, लेकिन घर की ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं है इलाज करा सके। उनकी पत्नी ने लोगों से आर्थिक मदद की अपील की है। ग्राम सनवाल निवासी मोहम्मद सलाम आजाद (45) पिछले पांच वर्ष पहले लकवा ग्रस्त हो गए थे। इलाज के बाद वह तेजी से स्वस्थ हो रहे थे। वहीं, कोरोना काल के दौरान नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच नहीं हो पाई। पिछले दिनों जब तबीयत खराब हुई तो स्वास्थ्य जांच कराई। इस दौरान पता चला कि किडनी खराब हो गई है, जिससे सप्ताह में तीन दिन डायलिसिस करना पड़ रहा है। इलाज में काफी खर्च हो रहा है, लेकिन आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। मोहम्मद सलाम आजाद का सनवाल की चौक में छोटी सी किराने की दुकान है, जिससे आजीविका चल रही थी। गंभीर बीमारी से आजीविका चलाना मुश्किल हो रहा है। दूसरी ओर गंभीर बीमारी के इलाज में काफी पैसा खर्च हो रहा है।

जांजगीर चांपा में सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना

जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिले में गुरुवार की रात चोरों ने शिक्षक के सूने मकान को निशाना बनाते हुए चार-पांच लाख रुपये के गहने और 12 हजार रुपये नकदी रकम पर हाथ साफ किया है। घटना वार्ड नंबर 18 केनाल सिटी के पास की है। चोरों ने कुंडी को काटकर घर के अंदर घुसकर चोरी की है। जब पति-पत्नी घर पहुंचे तो सामान कमरे के अंदर बिखरा हुआ था। अलमारी का दरवाजा खोलकर लॉकर से सोने-चांदी के जेवर की चोरी की गई है। चोरी की सूचना सिटी कोतवाली पुलिस को दी गई। शिक्षक नंद कुमार कश्यप ने बताया कि नैला में अपनी ससुराल पत्नी अनुराधा कश्यप के साथ गुरुवार की सुबह करीबन 10 बजे गए हुए थे और रात को वहीं रुके हुए थे। घर के सभी दरवाजों में ताला लगा हुआ था। सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था। शुक्रवार की सुबह करीबन नौ बजे नैला से अपने घर पहुंचे। घर के अंदर जाने पर पता चला कि चोरी हुई है। अलमारी में रखा सोने का हार, अन्य सोने-चांदी के जेवर और नकदी रकम 12 हजार रुपये की चोरी अज्ञात चोरों ने की।

पत्नी और बेटी का झोपड़ी में मिला जला हुआ शव

रायगढ़। घरघोड़ा थाना क्षेत्र के कमतरा गांव में एक ही परिवार के तीनों लोगों की लाश मिली है। मां और बेटी का झोपड़ी में जला हुआ शव मिला। वहीं, एक शख्स संतोष कुमार फांसी के फंदे पर लटका मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की बात कही जा रही है। हालांकि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार, कमतरा गांव में शुक्रवार की सुबह तीन लोगों की मौत के बाद सनसनी फैल गई है। इस पूरी घटना में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जिस घर में मां और बेटी की जली हुई लाश मिली है, वह घर पूरी तरह आग में जल चुका था और घर के पास ही एक पेड़ में युवक की फांसी पर लटकती हुई लाश मिली है। ग्रामीणों के अनुसार यह पूरा मामला हत्या के बाद आत्महत्या से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि यह पूरी घटना गुरुवार रात की है। शुक्रवार सुबह जब पुलिस गांव पहुंची, तब घर पूरी तरह जला हुआ था।

बदहाल सड़क, परेशान जनता और विकास के खोखले दावे

बलौदाबाजार। जिले में विकास की गाथा बड़े ही उत्साह के साथ मंत्री, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी प्रमुखता से कहते रहते हैं, लेकिन तस्वीर इसके ठीक उलट है। जिले में खराब और खस्ताहाल सड़कों से आम जनता त्रस्त है। आए दिन गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है। वाहन चालक भी बेपरवाह हैं। जनता अधिकारियों को आवेदन दे-देकर परेशान है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं।

सबसे ज्यादा खराब स्थिति बलौदाबाजार-भाटापारा मार्ग, बलौदाबाजार से सुहेला पड़कीडीह, हथबंद, सिमगा, बलौदाबाजार विकासखंड के ही ग्राम करमदा, गैतरा, भरसेला मार्ग है, जिस पर लोगों का चलना दूभर हो चुका है। उड़ती धुल और बड़े-बड़े गड्ढों से जनता परेशान है।

बलौदाबाजार-भाटापारा मार्ग ऐसा कि सामान्य आदमी भी मोटर साइकिल चलाये तो लगता है, तो लगता है कि नशा कर गाड़ी चला

रहा है, पर मजबूर है। यह जरूर है कि मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्री जिले में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के भूमिपूजन और लोकार्पण कर रहे हैं, पर सड़कों की स्थिति ठीक उल्टी है।

जनता और खासकर ग्रामीण जो कि सीमेंट संयंत्र के आसपास रहते हैं, उनका कहना है कि सड़क से उड़ती धूल से नहीं घर में बनने वाले खाद्य पदार्थ बड़ी, बिजौरी और अन्य सामान बना पा रहे हैं, और न ही कपड़े सूखा पा रहे हैं। घर का सदस्य जब बाहर जाता है, वह सही-सलामत आ पाएगा या नहीं इसका डर हमेशा बना रहता है, लेकिन आम लोगों की चिंता न तो प्रशासन को है और नहीं सीमेंट संयंत्रों को।

वाहन चालक कहते हैं कि जान जोखिम में डालकर वाहन चलाने को मजबूर हैं। कब गाड़ी खराब हो जाएगी या कब एक्सीडेंट हो जाएगा, हम नहीं जानते हैं। वहीं ग्रामीण महिला ने कहा कि न तो वह घरेलू सामान बना पाती है और न ही कपड़े सुखा पा रही है। इस कदर धूल है। जनसुनवाई के दौरान यह मामला लगभग हर किसी ने उठाया है।

वहीं सीमेंट संयंत्र में सामान लेकर आने वाले वाहनों पर न ही जिला प्रशासन और नहीं आरटीओ और पुलिस विभाग कार्रवाई करता है। हां, यह जरूर है कि पुलिस मोटरसाइकिल सवारों को शिक्षा जरूर देती है कि हेलमेट पहन कर वाहन चलाये और जुर्माना भी इन्हीं से वसूल रही है, पर ओव्हरलोड वाहनों पर जिले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह एक बड़ा सवाल आम जनता का है कि आखिर क्यों।

मछली पालन कर सालाना साढ़े पांच लाख रुपये कमा रहे कृषक जयराम

दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ सरकार कि ओर से मछुआरों और मत्स्य पालक कृषकों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कई रियायतें दी जा रही है। दंतेवाड़ा जिले के ग्राम मैलावाड़ा के प्रगतिशील कृषक जयराम कश्यप ने मत्स्य पालन के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए अन्य कृषकों के लिए प्रेरक बन गए है। पारंपरिक खेती से सीमित आय प्राप्त करने वाले जयराम ने 2017 में अपनी पुश्तैनी भूमि पर तालाब बनाकर मत्स्य पालन शुरू किया। उन्होंने मत्स्य विभाग के मार्गदर्शन में इन योजनाओं का लाभ उठाते हुए अपनी सवा एकड़ भूमि पर तालाब का निर्माण कराया और 2023-24 में 25 डिसमिल भूमि में पौंड-लाइनर भी स्थापित किया।

जयराम कश्यप ने सघन मत्स्य पालन तकनीक अपनाते हुए रोहू, कतला, मृगल और कॉमन कॉर्प जैसी उन्नत नस्लों का पालन किया। उनके पौंड-लाइनर में सारंगी

(फंगाल) जैसी मछलियों के बीजों को तैयार किया जाता है। तालाबों में ऑक्सीजन की सतत आपूर्ति और वैज्ञानिक तरीकों से मछलियों की बेहतर देखभाल की जाती है। कश्यप को मत्स्य पालन से सालाना साढ़े पांच लाख रुपये का मुनाफा हो रहा है, जो कि उनके कृषि आय से कई गुना अधिक है। उनके दोनों पुत्र इस व्यवसाय में सहयोग कर रहे हैं। स्थानीय बाजार में मछलियों की अधिक मांग के कारण उनकी मछलियां आसानी से बिक जाती हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य में मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने के लिए मछुआरों को तालाब निर्माण, उपकरण, परिपूरक आहार और मत्स्य बीजों के लिए अनुदान प्रदान किया जा रहा है। जयराम कश्यप ने बताया कि वे अपने तालाब के पास कुक्कुट शेड बनाकर आय के स्रोतों को और बढ़ाने के लिए प्रयासरत् है। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं और जयराम कश्यप जैसे प्रगतिशील किसानों के प्रयासों ने दंतेवाड़ा जिले में मत्स्य पालन को एक आकर्षक और स्थायी व्यवसाय बना दिया है। यह सफलता क्षेत्र के अन्य किसानों को भी मत्स्य पालन के प्रति प्रेरित कर रही है।

मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग और महिलाओं को 60 प्रतिशत तक अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है, जिससे इस वर्ग के लोग भी मछली पालन को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रहे हैं।

संक्षिप्त समाचार

ईवीएम से होगा नगरीय निकाय चुनाव जल्द अध्यादेश जारी करेगी सरकार

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार नगरीय निकाय चुनाव में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब राज्य में सभी शहरी निकायों के चुनाव ईवीएम से होंगे। इसकी तैयारी चुनाव आयोग ने शुरू कर दी है। नगरीय प्रशासन मंत्री, डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से कराया जाएगा। बीजेपी की कोर ग्रुप बैठक में इस निर्णय पर सहमति बनी थी। गौरतलब है कि 2019 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बैलेट पेपर से नगरीय निकाय चुनाव कराया था। अब साय सरकार ने निर्णय लिया है कि आगामी निकाय चुनाव ईवीएम के जरिए कराए जाएंगे। इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग प्रस्ताव बनाकर राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगा। आयोग के परीक्षण के बाद विधि विभाग की अनुमति मिलने पर अध्यादेश जारी किया जाएगा। ईवीएम से चुनाव कराने के पीछे की वजह यह है कि बैलेट पेपर से चुनाव के परिणामों की घोषणा में लंबा समय लगता है। 2010 में रायपुर महापौर चुनाव के दौरान भी देर रात तक मतगणना चली थी, जिसके बाद ईवीएम से चुनाव कराने का निर्णय लिया गया था। अब महापौर के पद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होने वाले हैं, जिसमें भारी मतदान की संभावना है, जिसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

डीएलएड परीक्षा 2024-25 के लिए आवेदन और नामांकन प्रक्रिया शुरू

रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) नामांकन और परीक्षा आवेदन प्रक्रिया की तिथियां घोषित कर दी हैं। डीएलएड के प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को अपने आवेदन ऑनलाइन भरने होंगे। मंडल ने प्रक्रिया को समयबद्ध और सुचारू बनाने के लिए महत्वपूर्ण तिथियों की सूची जारी की है। प्रथम वर्ष के परीक्षार्थियों ग्राह्यता/नामांकन के लिए ऑनलाइन 10 से 31 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षार्थी तीन से 18 फरवरी तक मंडल में नामांकन फार्म की हार्ड कॉपी जमा कर सकेंगे। प्रथम और द्वितीय वर्ष के मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन तीन से 20 मार्च तक आवेदन किया जाएगा और आवेदन फार्म की हार्ड कॉपी 21 से 28 मार्च 2025 तक मण्डल में जमा कर सकेंगे। विलंब से परीक्षा की हार्ड कॉपी जमा करने पर विलंब शुल्क 1540 रुपये प्रति परीक्षा की दर से आवेदन एक से नौ अप्रैल 2025 तक जमा किया जा सकता है।

धमतरी जिले में आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पद पर भर्ती

रायपुर। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी में सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसमें वार्ड के शिक्षित महिलाएं 23 जनवरी तक आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके लिए महिलाओं को कम से कम आठवीं पास होना अनिवार्य है। एकीकृत बाल विकास परियोजना नगरी के तहत आंगनबाड़ी केन्द्र बेलरगांव चालीपारा में आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पद पर भर्ती के लिए इच्छुक आवेदिकाओं से आगामी 23 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना नगरी ने बताया कि 18 से 44 वर्ष तक आयु की, उसी ग्राम और वार्ड की निवासी और शैक्षणिक योग्यता कम से कम आठवीं उत्तीर्ण आवेदिका आवेदन कर सकतीं हैं। आवेदन पत्र सीधे अथवा पंजीकृत डाक से जमा किया जा सकता है। आयु के संबंध में सक्षम प्राधिकारी कि ओर से जारी जन्म प्रमाण पत्र एवं मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड की अंकसूची ही मान्य की जाएगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय से संपर्क कर नियुक्ति नियमावली का अवलोकन किया जा सकता है।

मोवा ओवरब्रिज मरम्मत के बाद 24 घंटे भी नहीं चल पाई!, उखाड़ने लगी सड़क

रायपुर। राजधानी रायपुर के मोवा रेलवे ओवरब्रिज कई जगहों से जर्जर हो गया था। जिसका डामरीकृत सतह को उखाड़कर नया डामरीकरण मरम्मत का काम किया गया। ब्रिज की मरम्मत अछि तरह से हो इसके लिए तीन से आठ जनवरी तक ब्रिज को बंद कर काम कराया, लेकिन अब यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ब्रिज का नया डामरीकरण मरम्मत सही तरीके से एक दिन भी नहीं चल पाया और सड़क उखाड़ने लगा। इस घटना की खबर सामने आने पर ठेकेदार पुनः सही तरीके से उखड़ी हुई सड़क को फिर से मरम्मत का काम किया जाएगा। बता दें कि राजधानी रायपुर में मोवा रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर विद्यमान डामरीकृत सतह को उखाड़कर नया डामरीकरण मरम्मत का काम विगत तीन जनवरी से शुरू किया गया था। कार्य जल्द पूर्ण करने और यातायात के दबाव के कारण रात तीन से चार बजे तक डामरीकरण किया जा रहा था। वहीं सुबह देखने में आया कि डामर से कुछ जगह गिट्टी निकल रही है, जो कि डामर का मटेरियल अधिक गरम होने के कारण है। यह काम वर्तमान में प्रगतिरत है। काम अभी पूरा नहीं हुआ है। ओवरब्रिज के जिस हिस्से में डामर से गिट्टी निकल रही है, वहां के डामर को उखाड़ कर पुनः कार्य कराया जाएगा। ठेकेदार की ओर से किए गए कामों का भुगतान कार्य की गुणवत्ता के पूर्ण परीक्षण के बाद किया जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव 2.0 का किया आगाज

17 राज्यों के 1500 से ज्यादा उद्योगपति हुए शामिल, छत्तीसगढ़ में कोयला, पावर और बिजली की उपलब्धता : लखन लाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दो दिवसीय ऑल इंडिया स्टील कॉनक्लेव 2.0 का आयोजन किया जा रहा है। 10 और 11 जनवरी को यह कॉनक्लेव होगा। जिसमें 17 राज्यों से 1500 प्रतिनिधि शामिल हो रहे है। सेकेन्डरी स्टील में राष्ट्रीय स्तर का इतना बड़ा आयोजन करने का सौभाग्य छत्तीसगढ़ को मिला है। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री साय, मंत्री लखनलाल देवांगन और सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दीप प्रज्वलन कर की।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए स्वाभग्य का विषय है। अब तक का सबसे बड़ा स्टील कॉन्क्लेव यहां हो रहा है। 2025 के शुरुआत में हो रहा है। बहुत से उद्योगपति है। जिनसे मैं पिछले वर्षों से मिलता रहा हूं। कई सबमिट में उद्योगपतियों से मुलाकात होती रही है। इस कॉन्क्लेव में 17 राज्यों से उद्योगपति आए है। इस कॉन्क्लेव में 2 दिन आप सभी लोग विचार मंथन करने वाले है। 2 दिनों में आप लोग स्टील के सेक्टर में चर्चा करेंगे, यहां से नई दिशा मिलेगी ऐसा मैं विश्वास करता हूं। हमारा प्रदेश देश की इकनॉमी का

पावर हाउस है। दो दिन में हमारे प्रदेश की नई उद्योग नीति की चर्चा होगी। नए रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। हम लोग आपको हर योजना प्रारम्भ करेंगे। प्रदेश के हर उद्यमी को प्रदेश का ब्रांड एंबेसडर बनना होगा। छत्तीसगढ़ में अवसर के कई द्वार खुलने वाले है। जल्द ही हम ऊर्जा खरीदने वाले प्रदेश बनने वाले है।

मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में दूसरा कार्यक्रम है। उद्योग जगत के लोग जब छत्तीसगढ़ आते है तो यह गौरव की बात होती है। छत्तीसगढ़ सीधा-साधा प्रदेश है। यहां पर कोयला, पावर और बिजली की उपलब्धता है। सीएम के विशेष प्रयास से आज छत्तीसगढ़ विकास की उचांइयों को छू रहा है। हम सब लोगों ने आप सभी से चर्चा करके उद्योग नीति लागू किया है। उद्योग नीति में बहुत सारे योजना लाने का काम किया है। छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों को पता है कैसे उद्योग नीति कैसे तैयार किया गया है। जिसके बारे में बाहर से पहुंचे उद्योगपतियों को बताएं, और वे छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाए। सीएम के साथ मिलकर अच्छी उद्योग नीति का निर्माण किया है। बेहद स्टील सेक्टर और उद्योग नीति की स्थापना हमने की है। उद्योगित प्रोत्साहन का काम हमने किया है। अनुदान की भी व्यवस्था हमने रखी है। स्टील उद्योग में 10 से 15 वर्षों तक बिजली बिल में लगने वाली विद्युत शुल्क में भी छूट का प्रावधान हमने रखा है। स्टील उद्योग में 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान है।

रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा की मोदी 3.0 चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जिस स्पीड से डेवलपमेट की ओर ले जा रहा है। ये स्टील इंडस्ट्री के तेजी से आगे बढ़ने का एक बड़ा कारण हैं। छत्तीसगढ़ में सभी चीजें है। सीमेंट, पानी, स्टील भी है। नया समय नया जमाना आ गया है। हमको सीएसआर से हमने शहर गांव की ओर जाना होगा। हमारे सराउंडिंग को कैसे डेवलप कर सकते है। हम लोगों को ड्रिंकिंग वाटर कैसे उपलब्ध करा सकते है। अगर हमको उद्योगों को आगे बढ़ाना है तो हमें इन दिशाओं में काम करना होगा। छत्तीसगढ़ में उद्योग है, आयरन ओर, बिजली और कोयला है, लेकिन कुछ कठिनाईयों का सामना करते हैं। आने वाले समय में केंद्र सरकार के साथ में भी आपके साथ रहूंगा ताकि इन समस्याओं को सामाधान हो सके, जिससे छत्तीसगढ़ के उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

छत्तीसगढ़ स्टील रि-रोलर्स एसोसिएशन और सहयोगी है। छत्तीसगढ़ स्पॉज आयरन मैन्युफैक्चरर्स जिएशन व छत्तीसगढ़ मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन सहित स्टील प्लांट के सहयोगी शामिल हुए।

छत्तीसगढ़ में भाजपा चलाएगी संविधान गौरव अभियान

भाजपा नेताओं ने कहा- आरक्षण विरोधी है कांग्रेस का डीएनए

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भाजपा संविधान गौरव अभियान चलाएगी। इसे लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, भाजपा नेता नवीन मार्कण्डेय सहित अन्य भाजपा नेताओं ने प्रेस कान्फ्रेंस की। संविधान गौरव अभियान के छत्तीसगढ़ प्रभारी पासवान ने कहा, कांग्रेस के लोग संविधान को अपनी ठेकेदारी समझते हैं। कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर का कभी सम्मान नहीं किया। भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार ने हमेशा उनको और उनकी स्मृतियों को सम्मान देने का काम किया है।

उन्होंने कहा, संविधान गौरव अभियान 26 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान बाबा साहेब अम्बेडकर के काम और उनकी बातों को लेकर लोगों के पास जाएंगे। कांग्रेस के भ्रम फैलाने के रवैये को भी लोगों को बताएंगे।

भाजपा नेताओं ने कहा, राहुल गांधी ने अपनी हालिया अमेरिकी यात्रा के दौरान कहा था कि वह 'आरक्षण हटा देंगे। ये वही धुन है, जो राहुल गांधी का परिवार नेहरू के जमाने से गाता आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने 57 वर्षों तक देश पर शासन किया, लेकिन इस दौरान उसने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया और सामाजिक उद्देश्यों की उपेक्षा की। कांग्रेस ने कभी भी संविधान के मूलभूत आरक्षण सिद्धांतों को सही भावना और रूप में लागू करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं दिखाई।

छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार हो रहा है विस्तार

अब दूसरे राज्यों से भी सर्जरी के लिए अम्बेडकर अस्पताल पहुंच रहे लोग

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयासों से छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर राज्य के सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं में दिनों दिन वृद्धि हो रही है। इसका नतीजा है कि स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में पंडित नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय से संबध्द डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय के प्रति लोगों का विश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस संस्थान के विभिन्न विभागों के डॉक्टरों की समर्पित टीम एवं पैरामेडिकल स्टाफ की बदौलत जटिल से जटिल मेडिकल केस में डॉक्टरों को सफलता मिली है। यही वजह है कि न केवल राज्य बल्कि पड़ोसी राज्यों के मरीज भी यहां उपचार के लिए पहुंच रहे हैं।

इसी कड़ी में हाल ही में अम्बेडकर अस्पताल के हार्ट सर्जरी विभाग के डॉक्टरों की टीम ने मध्यप्रदेश निवासी एक मरीज की एक बार फिर सफल ओपन हार्ट सर्जरी की है। हार्ट सर्जरी का यह केस इसलिए विशेष है क्योंकि मरीज का हृदय मात्र 35

प्रतिशत ही काम कर रहा था। मरीज को रूमैटिक हार्ट डिजीज नामक बीमारी थी जिसके कारण मरीज के दो वाल्व क्रमशः एओर्टिक वाल्व और माइट्रल वाल्व में सिकुड़न थी एवं तीसरे वाल्व ट्राइकस्पिड वाल्व में लीकेज था। विभागाध्यक्ष हार्ट सर्जरी डॉ। कृष्णकांत साहू के नेतृत्व में हुए इस ऑपरेशन में मरीज के हृदय के इन दोनों वाल्व को टाइटेनियम मेटल के वाल्व से बदला गया एवं तीसरे वाल्व को रिपेयर किया गया। सर्जरी के पश्चात् मरीज के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है एवं एक-दो दिन बाद मरीज को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। यह ऑपरेशन शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान योजना के अंतर्गत पूर्णतया निशुल्क हुआ है।

अम्बेडकर अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर कहते हैं कि अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों के साथ हमारी कोशिश रहती है कि मरीजों को बेहतर उपचार सुविधा का लाभ मिले। मध्यप्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों के मरीजों का भी आयुष्मान योजना के अंतर्गत यहां उपचार संभव हो रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं के ऐसे विस्तार ने अम्बेडकर अस्पताल के प्रति लोगों का भरोसा बरकरार रखा है।

मध्यप्रदेश के अनूपपुर निवासी 52 वर्षीय मरीज को चार साल से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जरा सा भी काम करने पर सांस फूल रहा था। शुरूआत में स्थानीय डॉक्टरों द्वारा अस्थमा की बीमारी की तरह उपचार किया गया। बाद में दूसरे डॉक्टरों से जांच कराने पर पता चला कि मरीज के हार्ट के चार में से तीन वाल्व खराब हो गये हैं। चूंकि 3 वाल्व बदलना बहुत ही चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन होता है इसलिए मरीज के शुभचिंतकों ने उसे अम्बेडकर अस्पताल जाने की सलाह दी।

गौकशी और गौ तस्करी के विरोध में सर्व हिंदू समाज ने किया प्रदर्शन

कहा- गौ माता की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता, अपराधियों को मिले उम्रकैद या फांसी

रायपुर। गौ माता की हत्या और गौ तस्करी के बढ़ते मामलों के विरोध में आज सर्व हिंदू समाज ने रायपुर में बड़ा प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोगों के साथ धर्माचार्य संत, समाजसेवी, युवा और महिलाएं राजधानी के घड़ी चौक पर एकत्रित हुई। इसके बाद सर्व हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक में चक्काजाम किया। फिर जुलूस के रूप में एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। समाज के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की।

विभिन्न क्षेत्रों से आए लोग पारंपरिक वेशभूषा में हाथों में झंडे और बैनर लिए अपनी मांगों को बुलंद की। पूरा क्षेत्र गौ माता की जय और गौ हत्या बंद करो के नारों से गूंज उठा। प्रदर्शन के दौरान सर्व हिंदू समाज ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने शीघ्र कदम नहीं उठाया तो यह आंदोलन और भी व्यापक और उग्र रूप धारण करेगा। प्रदर्शनकारियों ने एक स्वर में कहा कि गौ माता की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। यह प्रदर्शन केवल विरोध नहीं, बल्कि हिंदू समाज की एकजुटता और संकल्प का प्रतीक था। रायपुर के घड़ी

चौक से एसपी कार्यालय तक का यह शांतिपूर्ण विरोध छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ।

संयोजक घनश्याम चौधरी ने कहा कि इस ऐतिहासिक प्रदर्शन की अगुवाई संतों और धर्माचार्यों ने की। संतों ने अपने विचार रखते हुए गौ माता की सुरक्षा को प्रत्येक हिंदू की नैतिक और धार्मिक जिम्मेदारी बताया। उन्होंने कहा, गौ हत्या न केवल हमारे धर्म का अपमान है बल्कि यह समाज की जड़ों पर हमला है। उनके प्रेरणादायक शब्दों ने आंदोलन में मौजूद लोगों को नई ऊर्जा प्रदान की। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने कहा, यह आंदोलन समाज के हर वर्ग के लिए एक प्रेरणा है कि धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हम सभी को एकजुट होकर खड़ा होना होगा।

ये हैं सर्व हिंदू समाज की प्रमुख मांगें

गौ हत्या और तस्करी के अपराधियों को उम्रकैद या फांसी की सजा दी जाए।

माफिया सरगनाओं पर बुलडोजर कार्रवाई की जाए।

इस घिनौने रैकेट में शामिल आरोपियों के अवैध संपत्तियों को जब्त किया जाए।

जिस थाना क्षेत्र में गौकशी हुआ वहां के पुलिस अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए।

रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी के रैकेट को खत्म करने विशेष अभियान चलाया जाए।

एसपी ने दोषियों पर कठोर कार्रवाई का दिया आश्वासन

पुलिस अधीक्षक और प्रशासनिक अधिकारियों ने आंदोलनकारियों से मुलाकात की और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। एसपी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष रणनीति बनाई जाएगी।

गौ माता की तस्करी करने वाले या तो सुधर जाएं, या छोड़ दें छत्तीसगढ़ः साय

रायपुर। प्रदेश में गौमाता की तस्करी और गौमांस की बिक्री करने वालों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि गौमाता की तस्करी करने वाले या तो सुधार जाएं या छत्तीसगढ़ छोड़ दें। ऐसे अपराधियों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि राजधानी रायपुर में गौमांस बिक्री के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह न केवल गंभीर अपराध है, बल्कि यह सनातन आस्था और सामाजिक सद्भाव को गहरा आघात पहुंचाने वाला कृत्य है। गौमाता की तस्करी करने वाले या तो सुधर जाएं या छत्तीसगढ़ छोड़ दें। ऐसे अपराधियों की प्रदेश में कोई जगह नहीं है।

बता दें कि रायपुर के मोमिनपारा इलाके में बीती देर रात गौकशी से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया था, जहां एक घर से बड़ी मात्रा में गौ मांस बरामद हुआ था। गौकशी का मामला तब उजागर हुआ जब पुलिस ने मोमिनपारा में छापा मारा। बताया जा रहा है गौ मांस बेचने के लिए दो गायों की गौकशी की गई थी। पुलिस ने मौके से 226.6 किलो मांस जब्त किया था। इस मामले में पुलिस ने कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है।

रायपुर में गौ-मांस बेचने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। रायपुर के मोमिनपारा में एक घर के भीतर गौ-मांस बेचने के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी पुलिस के रेड पड़ते ही भाग गए थे। इस मामले में देर रात तक आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर गौ-सेवकों ने जमकर बवाल किया। पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को अलग-अलग ठिकानों से गिरफ्तार कर लिया।

छत्तीसगढ़ में जमीनी विवाद में हुई हिंसक झड़प

- दबंगों ने पति-पत्नी और बेटे को पीट-पीटकर मार डाला

सूरजपुर। प्रतापपुर थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान मां-बेटे की मौके पर मौत हो गई और पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अंबिकापुर पहुंचने पर घायल पिता की भी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जानकारी के मुताबिक, जगन्नाथपुर के डूबकापारा में संयुक्त खाते की जमीन को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में विवाद चल रहा था। विवादित भूमि पर खेती करने उमेश टोप्पो, नरेश टोप्पो अपनी मां बसंती टोप्पो और पिता माघे

टोप्पो के साथ पहुंचे थे। दोपहर करीब एक बजे माघे टोप्पो के रिश्ते में भाई के परिवार के छह से सात सदस्य भी मौके पर पहुंच गए।

विवाद कुछ देर में हिंसक झड़प में बदल गया। दूसरे पक्ष ने माघे टोप्पो के परिवार पर टांगी और लाठियों से हमला कर दिया। हमले में बसंती टोप्पो (55) एवं नरेश टोप्पो (30) की मौके पर मौत हो गई। दोनों मृतकों के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं, माघे टोप्पो (57) गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले के दौरान उमेश टोप्पो ने भागकर जान बचाई और ग्रामीणों को सूचना दी।

घटना की सूचना मिलने पर खड़गवां चौकी प्रभारी योगेंद्र जायसवाल की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल माघे टोप्पो को इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए रवाना किया। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अंबिकापुर पहुंचने पर घायल माघे टोप्पो की भी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए हैं। प्रतापपुर से भी पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि विवादित जमीन जगन्नाथपुर कोल माइंस के सामने है। विवादित भूमि पर हमलावरों ने खेती करने से मना किया था। आहत परिवार खेती करने के लिए पहुंच गया तो विवाद हिंसक में बदल गया।

कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष (जिला निर्माण समिति) जिला कोण्डागांव

// मैनुअल पद्धति चतुर्थ जोनल निविदा आमंत्रण//

एन.आई.टी. क्रमांक / 15,16 & 17 / जि0नि0स0/निविदा/2024-25 कोण्डागांव, दिनांक 09/01/2025

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से कार्यालय जिला निर्माण समिति कोण्डागांव के कार्यालय में दो लिफाफा पद्धति से प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग रायपुर (छ.ग.) के द्वारा जारी भवन-सड़क-पुलिया निर्माण कार्य हेतु दिनांक दिनांक 01.01.2015 से प्रचलित व प्रभावशील दर अनुसूची एवं प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग रायपुर (छ.ग.) के द्वारा जारी विद्युतीकरण कार्य हेतु दिनांक 01. 06.2020 से प्रभावशील दर अनुसूची से निविदा आमंत्रण तिथि तक संशोधित दर अनुसूची पर निविदा प्रपत्र 'अ' में प्रतिशत के आधार पर दर निम्नांकित कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग में एकीकृत पंजीयन प्रणाली में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं स्पीड पोस्ट से आमंत्रित की जाती है।

01. कार्यालय में निविदा लिफाफे प्राप्ति की अंतिम तिथि- 15/01/2025 संध्या 5:00 बजे तक।
02. कार्यालय में निविदा लिफाफे खोले जाने की तिथि- 16/01/2025 प्रातः 11.30 बजे।

क्र.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (राशि रू0 लाख में)
1	2	3
01	रु. 10.00 लाख से कम लागत के विभिन्न निर्माण भवन/मंच/पुलिया/बाउंड्रीवाल/ नाली/सड़क एवं अन्य प्रकार के निर्माण कार्य विद्युतीकरण सहित विकासखण्ड केशकाल।	100.00
02	रु. 10.00 लाख से कम लागत के विभिन्न निर्माण भवन/मंच/पुलिया/बाउंड्रीवाल / नाली/सड़क एवं अन्य प्रकार के निर्माण कार्य विद्युतीकरण सहित विकासखण्ड फरसगांव।	100.00
03	रु. 10.00 लाख से कम लागत के विभिन्न निर्माण भवन/मंच/पुलिया/बाउंड्रीवाल/ नाली/सड़क एवं अन्य प्रकार के निर्माण कार्य विद्युतीकरण सहित विकासखण्ड बड़ेराजपुर।	100.00

टीपः- उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति (परिशिष्ट- 2.10 एवं निविदा दस्तावेज परिशिष्ट-2.13) एवं अन्य जानकारियां कार्यालयीन अवधि में कार्यालय-जिला निर्माण समिति, जिला कोण्डागांव में अथवा ऑनलाईन www.kondagaon.gov.in वेबसाइट में दिनांक 09.01.2025 से देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है।

कलेक्टर एवं अध्यक्ष
(जिला निर्माण समिति) जिला कोण्डागांव

जी-242505220/7

असभ्य नेताओं के बिगड़े बोलों पर लगे लगाम

रजनीश कपूर

चुनावी सभा हो या संसद सदन जब भी नेताओं के बोल बिगड़ते हैं तो सुर्खियां बनते देर नहीं लगती। परंतु सोचने वाली बात यह है कि जहां एक ओर हमारे देश में राजनेताओं की एक जमात ऐसी थी जो नैतिकता का पालन करती थी, वहीं दूसरी ओर बीते कुछ वर्षों से राजनेताओं के बयानों में आपको अभद्रता के कई उदाहरण मिलेंगे। दल चाहे कोई भी हो नेताओं की जुबान फिसलते देर नहीं लगती। फिर वह चाहे किसी पुरुष नेता का महिला के संदर्भ में दिया गया बयान हो, किस धर्म या जाति विशेष के लोगों के खिलाफ दिया गया बयान हो या किसी महिला नेता का किसी आम आदमी को धमकाने वाला बयान हो। नेता अपनी कुर्सी की गर्मी और अहंकार के चलते सभी हदें पार कर देते हैं। बीते कुछ दिनों में अलग-अलग दलों के नेताओं द्वारा जिस तरह की बयानबाजी देखने को मिली है उससे यह बात तो साफ है कि नेता सुर्खियों में बने रहने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। ऐसे में देखना यह है कि राजनीतिक दलों का शीर्ष नेतृत्व ऐसे बेलगाम नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। यदि कोई भी दल इस बात की दुहाई दे कि वे महिला सम्मान के प्रति कटिबद्ध है और वहीं उसी के दल के नेता किसी जनसभा में किसी सड़क की तुलना विपक्षी दल की किसी महिला नेता के 'गालों' से करता है तो यह बात न सिर्फ निंदनीय होनी चाहिए बल्कि ऐसे नेता को उसके शीर्ष नेतृत्व से कड़ी फटकार और सजा भी मिलनी चाहिए जिससे कि अन्य नेताओं को सबक मिले। परंतु क्या ऐसा हुआ या ऐसा होता है? यदि इसका उत्तर 'नहीं' है तो यह बात स्पष्ट है कि ऐसे अनैतिक नेताओं को उनके शीर्ष नेतृत्व की पूरी हमदर्दी और आशीर्वाद प्राप्त है। पिछले दिनों में जहां एक दल के नेता ने एक महिला नेता और एक महिला मुख्यमंत्री के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया वहीं एक अन्य दल के नेता ने एक सभा में अपने क्षेत्र के वोटरों को ही दोषी ठहराया। इतना ही नहीं उनकी तुलना 'वैश्या' से भी कर डाली। उसी राज्य में एक अन्य दल के वरिष्ठ नेता ने भी अपने वोटरों को इस तरह धमकाया कि यह बयान भी सुर्खियों में छा गया। इस वरिष्ठ नेता ने तो यहां तक कह डाला कि सिर्फ इसलिए कि आपने वोट दिया इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेरे मालिक हैं। क्या आपने मुझे अपना नौकर बना लिया है? यह बात तो जग-जाहिर है कि चुनावी दिनों में हर नेता अपने वोटरों के आगे-पीछे घूमते हैं। उन्हें रिझाने के लिए क्या-क्या नहीं करते। परंतु जैसे ही वे सत्ता में आते हैं तो अपना असली रंग दिखाने में पीछे नहीं हटते। ऐसे में कबीर दास जी का यह दोहा याद आता है, 'ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोये। औरन को शीतल करे, आपहुं शीतल होए।।' जो हमें बचपन से ही सिखाता आया है कि चाहे कुछ भी हो हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को आनंदित करे। जहां मीठे वचन सुनने वालों को सुख देते हैं, वहीं हमारे मन को भी आनंदित करते हैं। परंतु क्या हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि इसका अनुसरण कर रहे हैं? या सत्ता के अहंकार में आपा खो रहे हैं।एक समय था जब नेता अपने क्षेत्र की जनता को सिर-आंखों पर बिठा कर रखते थे। उनकी हर छोटी-बड़ी समस्या का हल निकालने के लिए हर कदम उठाते थे। अपने क्षेत्र के वोटर के खुशी और गम में भी परिवार की तरह ही शामिल हुआ करते थे। परंतु आजकल कुछ नेताओं को छोड़ कर ऐसे नेता आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे। पुरानी पीढ़ी के नेता जिस सादगी से चुनाव के पहले रहते थे, चुनावों में जीतने के बाद भी वे उसी सादगी से ही नजर आते थे। परंतु आजकल के नेता चुनावों में जितनी भी सादगी दिखाएं, चाहे चुनाव जीतने के बाद सादगी से रहने के जितने भी वादे क्यों न करें, चुनाव जीतते ही अपने किए वादों से मुकरने में क्षण भर भी नहीं लगाते। वे जनता को अपनी मुट्ठी में रखने का झूठा एहसास बनाए साथ रहते हैं। भारत जैसे देश के लिए कहा जाता है कि 'चार कोस पर बदले पानी आठ कोस पर वाणी' यानी हमारे देश में विविधताओं का होना प्राचीन युगों से चला आ रहा है। भारत में अनेक धर्मों, जातियों, विचारों, संस्कृतियों और मान्यताओं से संबंधित विभिन्नताएं हैं। किन्तु उनके मेल से एक खूबसूरत देश का जन्म हुआ है, जिसे हम भारत कहते हैं। भारत की ये विविधताएं एकता में बदल गई हैं, जिसने इस देश को विश्व का एक सुन्दर और सबल राष्ट्र बना दिया है। हमारे द्वारा चुने गए नेता, चाहे किसी भी दल के क्यों न हों, चुनाव जीतते ही यदि अपनी असभ्यता का परिचय देने लग जाएं और उनके दल द्वारा उन्हें किसी भी तरह दंड न दिया जाए तो अगली बार जब भी ऐसे नेता जनता

देश की सियासत में दिल्ली की अहमियत

रशीद किदवई

दिल्ली बेशक एक छोटा राज्य है, मगर इसकी सियासत के मायने बहुत बड़े हैं। दिल्ली सरकार की राजनीतिक शक्तियां सीमित होती हैं, कई प्रशासनिक फैसलों में उपराज्यपाल का सीधा दखल रहता है, लेकिन इसके बावजूद यहां की सियासत से ही पूरे देश की राजनीति की दिशा और दशा तय होती है। आज की राजनीतिक असहिष्णुता के इस दौर में इस बार के दिल्ली चुनाव और भी अहम हो जाते हैं। देश में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त छह दलों में से तीन यहां पर जोर-आजमाइश कर रहे हैं, पर मुख्य मुकाबला अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) और भाजपा के बीच ही है। पिछले दो विधानसभा चुनावों में क्लीन स्वीप करने वाली सत्ताधारी आप आज अनेक समस्याओं से घिरी हुई है। कथित शराब घोटाले में केजरीवाल का नाम आने और जेल जाने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तक देना पड़ा और आतिशी को 'खड़ाऊ मुख्यमंत्री' बनाया गया, मगर केजरीवाल और 'आप' एक-दूसरे के पूरक हैं। इसलिए इन चुनावों में पार्टी ने 'फिर केजरीवाल' का नारा दिया है।

केजरीवाल की सत्ता में वापसी का मतलब होगा केंद्र के साथ टकराव का लगातार जारी रहना, बल्कि उसमें और बढ़ोतरी होना। केंद्र और दिल्ली राज्य के बीच जारी यह दंगल जनता की नजरों से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में यह प्रश्न भी उठता है कि क्या जनता फिर से ऐसी सरकार को चुनना चाहेगी, जिसकी केंद्र सरकार के साथ सियासी 'तू तू-मैं मैं' ही चलती रहे और राज्य के विकास कार्यों में अड़ंगा डलता रहे या फिर वह ऐसी सरकार चाहेगी, जिसे केंद्र का वरदहस्त प्राप्त हो। इस नैरेटिव से जूझना केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। फिर शराब घोटाले में केजरीवाल को मिली जमानत को लेकर उन पर बहुत सारी शर्तें लागू हैं, जो उनके लिए व्यावहारिक समस्याएं बन सकती हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें कई सारी फाइलें देखनी होंगी। यह भी विमर्श का एक मुद्दा बन सकता है और अगर पढ़े-लिखे मतदाता मदतान करने से पहले इन व्यावहारिक पहलुओं को तौलकर मतदान करते हैं, तो केजरीवाल के लिए दिक्कतें पैदा हो सकती हैं।

महिलाओं को सम्मान निधि का सियासी कार्ड मध्य प्रदेश, हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र के चुनावों तक में बड़ी सफलता से चला है और उन राज्यों में भाजपा की जीत में यह बड़ा फैक्टर रहा है। अब केजरीवाल ने महिलाओं को हर माह 2100 रुपये देने की 'महिला सम्मान योजना' लागू करने का वादा किया है। पर मजेदार बात यह भी है कि भाजपा द्वारा यह आरोप लगाने के बाद कि आतिशी सरकार महिला सम्मान योजना के फर्जी कार्ड बनवा रही है, दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग को विज्ञापन देकर यह कहना पड़ा कि इस तरह की कोई योजना अभी अधिसूचित नहीं की गयी है। इससे एक वर्ग में दुविधा बढ़ी है, जिसका भाजपा लाभ उठाना चाहेगी।

प्रश्न यह भी है कि चाहे केंद्र के साथ दिल्ली सरकार के टकराव का मसला हो या 'महिला सम्मान योजना' को लेकर विवाद खड़ा करने की मंशा, भाजपा को अपनी इस नकारात्मक राजनीति से लाभ मिलेगा या यह उसके लिए बूमरेंग साबित होगी? यह भी ये चुनाव तय करेंगे और इसी से उसकी आगे की राजनीति भी निर्धारित होगी। यह बिल्कुल साफ है कि दिल्ली राज्य की सत्ता में आने को लेकर भाजपा की व्यग्रता बहुत बढ़ गयी है। दिल्ली में भाजपा पिछले छह चुनावों में सरकार नहीं बना पायी है। बीते दो चुनावों से तो भाजपा की स्थिति बेहद कमजोर रही है। लोकसभा चुनावों में शानदार विजय हासिल करने के बावजूद राज्य चुनावों में उसका सूपड़ा साफ होता रहा है।

भाजपा सांप्रदायिक नैरेटिव के आधार पर आज ऊपर से भले ही मजबूत नजर आती है और महाराष्ट्र में 'बंटेंगे तो कटेंगे' या 'एक हैं तो सेफ हैं' जैसे नारों ने उसे सफलता भी दिलायी है, पर भाजपा के लिए समस्या यह है कि दिल्ली में स्वयं अरविंद केजरीवाल पुजारियों और ग्रंथियों को मानदेय देने की बात कर रहे हैं। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर कांग्रेस को हराने में तो भाजपा को दिक्कत नहीं होती है, पर केजरीवाल की पार्टी पर अब तक वह किसी एक धर्म विशेष का तुष्टीकरण करने का आरोप नहीं लगा पायी है। केजरीवाल स्वयं को हनुमान भक्त बताते हुए सार्वजनिक तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने जैसी नाटकीयता रचने से भी गुरेज नहीं करते हैं। इससे भाजपा 'आप' के खिलाफ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का वैसा कार्ड नहीं चल पाती है, जो उसे कांग्रेस के खिलाफ चलाने में आसानी होती है।

भाजपा इस बार दिल्ली में उस रणनीति पर भी चल रही है कि कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहे। पिछले दो चुनावों में कांग्रेस का स्कोर जीरो रहा है। वोट प्रतिशत भी चार-पांच प्रतिशत के आसपास रहा है। भाजपा को डर इस बात का है कि कहीं इसमें से भी दो-ढाई प्रतिशत केजरीवाल के खाते में ना चले जाएं। इसलिए भाजपा चाहती है कि वहां वोटों में कांग्रेस की हिस्सेदारी बढ़कर सात-आठ प्रतिशत हो जाए। यदि ऐसा होता है, तो इसका सीधा नुकसान 'आप' को होगा। इसी को भांपते हुए केजरीवाल ने भी भाजपा और कांग्रेस पर मिलीभगत के आरोप लगाने शुरू कर दिये हैं। इसके जरिये वह भाजपा विरोधी कांग्रेस के मतदाताओं को यह संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब एक तरह से भाजपा को वोट देना होगा।

जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, उसके स्थानीय नेता चाहते हैं कि उन्हें केजरीवाल के खिलाफ जमकर बात करने की स्वतंत्रता मिले, पर मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी जैसे राष्ट्रीय नेता एक बड़ी तस्वीर की ओर देख रहे हैं। उनकी मंशा है कि भाजपा किसी भी कीमत पर दिल्ली न जीत पाए, भले ही कांग्रेस का स्कोर जीरो पर बरकरार रहे, क्योंकि दिल्ली जैसे 'आप' के गढ़ में भाजपा की जीत आगामी बिहार चुनावों में इंडिया गठबंधन के सामने और मुश्किल हालात पैदा कर देगी। हरियाणा की राजनीति पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि वहां कांग्रेस के भीतर काफी खटपट चल रही है। भाजपा की जीत से वहां कांग्रेस के असंतुष्ट नेता एक क्षेत्रीय पार्टी के गठन के लिए और फिर भाजपा के साथ पींगे बढ़ाने को प्रेरित हो सकते हैं।

इधर, केजरीवाल परोक्ष रूप से यह नरैटिव भी रच रहे हैं कि यदि दिल्ली में वह हार गये, तो अगला नंबर ममता बनर्जी व स्टालिन समेत तमाम क्षेत्रीय नेताओं का आ सकता है और इससे क्षेत्रीय राजनीति का मर्सिया पढ़े जाने की शुरुआत हो सकती है। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जैसे क्षत्रपों द्वारा उन्हें समर्थन देने की घोषणा को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है।

एकात्मता के स्वर — उपनिषद्

उपनिषद् समूचे भारतीय तत्त्व चिंतन का आधार है। आदिकाल से मानव के मन में सृष्टि के रहस्यों को जानने की जिज्ञासा का उत्तर ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में है। इन सूक्तों का स्पष्टता से विस्तारपूर्वक जहाँ समाधान किया गया है वे ही उपनिषद् कहलाये।

ऋषियों ने कितनी अनुभूति कर चिंतन द्वारा उस तत्त्वज्ञान को प्रकट किया गया होगा कि विश्व के अनेक मूर्धन्य चिंतक उनको जानने की इच्छा से आकर्षित हुए। दाराशिकोह ने उनका फारसी भाषा में अनुवाद किया, जिसको पढ़ द्रवीभूत हुए फ्रेंच लेखक दुपेरोन ने उसका लैटिन भाषा में अनुवाद किया जो सन् 1802 में स्ट्रासबर्ग प्रेस में छपा। लैटिनग्रन्थ ओपेनरवत् जब प्रसिद्ध जर्मन दर्शनिक शोपेनहॉवर ने पढ़ा तो उसके उद्गार थे-उपनिषद् मानव बुद्धि की सर्वोच्च अभिव्यक्ति हैं।

ज्ञातव्य है कि उपनिषदों की श्रुतियाँ साक्षात् अनुभवजन्य होने से अतर्क्स मानीं जाती हैं। इसमें सभी अतिमानवीय विचार हैं। साधारणतया कहा जाता है कि जो तत्त्व या सत्य को अनुभव (जान लेता) कर लेता है उसकी स्थिति गूंगे के खाए गुड़ की सी हो जाती है। ज्यों गूंगा मीठे फल को रस अन्तर्गत ही भावै परन्तु भारतीय ऋषियों ने उस अतिउत्तम गोपनीय ज्ञान को भी जन साधारण को कहकर, शिष्यों को देकर जन सामान्य को उपलब्ध करा दिया।

उपनिषदों की संख्या एक सी आठ से लेकर दो सौ बीस तक कही गयी है। यूँ तो उपलब्ध सभी ज्ञान के स्रोत होने से महत्त्व के हैं पर ग्यारह उपनिषद् प्रमुख है। जिन पर आद्यशंकर ने भाष्य लिखा है। ये उपनिषद् हैं ईशोपनिषद्, केनोपनिषद्, कठोपनिषद्, मुण्डकोपनिषद् माण्डूक्योपनिषद्, एतरेयोपनिषद्, तैत्तिरीयोपनिषद्, प्रश्नोपनिषद्, छान्दोग्योपनिषद्, बृहदारण्यकपोनिषद् और श्वेताश्वतरोपनिषद् । इन उपनिषदों में जीव, जगत व परमात्मा का वैज्ञानिक विश्लेषण है। विज्ञान में एकत्व की खोज की तरह ही उपनिषदों में अंतिम एकत्व का प्रतिपादन किया गया है।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

(गतांक से आगे...)

(19) एक पुराण की कही दूसरा नहीं मानता, किसी देवता की एक निन्दा करना है दूसरा उसको अच्छा कहता है, इत्यादि नाना द्वेषयुक्त विरोध होने से पुराणों का कर्ता ब्यास नहीं हो सकता, बल्कि अनेक साम्प्रदायिक लोग हैं।

(20) प्रतिवादी को पुराणों में परस्पर विरोध जंचता है, परन्तु कभी वेदोक्त देवचरितों की भी तुलना को है, जहाँ एक ही मन्त्र में आपकी दृष्टि से देखने पर परस्पर विरोध की पराकाष्ठा दीख पड़ेगी। यथा- [क] अजायमानो बहुधा विजायते। (गनु0 31) [ख] एक एव रुद्रोऽवतस्थे न द्वितीयः। [ग] असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अधिभूम्याम्।

अर्थात्- (क) वह परमात्मा अजन्मा है और बहुत प्रकार से जन्म लेने वाला है। (ख) अकेले रुद्र भगवान् खड़े रहे दूसरा कोई नहीं था । (ग) भूमि पर अगणित हजारों रुद्र (स्थित हुवे)। यहाँ अजन्मा को जन्मधारी और एक को अनेक बताया गया है। मन्त्र का एक भाग दूसरे भाग का कहा नहीं मानता। क्या वेदों को भी आपकी कल्पना के अनुसार अनेक पुरुषों की कृति मान लिया जाय ? प्रतिवादी महाशय, कुछ तो विचार से आक्षेप घड़ा होता ? चले थे पुराणों को आधुनिक सिद्ध करने, उल्टा वेदों पर ही चौका लगा बैठे !

वास्तव में वेदादि सभी ग्रन्थों में भावना-विशेष से एक ही पदार्थ को अनेक दृष्टियों से वणित किया जाता है। इसी प्रकार पुराणों में भी अद्वितीय परमात्मा को ही अनन्त शक्तियों का भण्डार होने के कारण अनेक प्रकार से कहा है।

यद्यपि वर्णन सम्बन्धी नानात्व का अन्त में एक अद्वितीय ब्रह्म में पर्यवसान हो जाता है, तथापि व्यवहार दशा में उस स्वाभाविक अनेकत्व का परिहार कोई कर नहीं सकता।

क्रमशः ...

लाल बहादुर शास्त्री स्मृति दिवस

अंकित सिंह

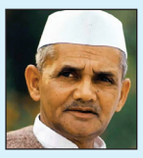

देश के दूसरे प्रधानमंत्री स्व. लाल बहादुर शास्त्री का आज 11 जनवरी को स्मृति दिवस है। पूरा देश उन्हें शिद्दत से याद करेगा। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र जब भी होता है तो उनके साधारण जीवन और मजबूत इरादों की बात जरूर की जाती है। छोटे से कार्यकाल में ही उन्होंने देश को नई दिशा देने की कोशिश की। साथ ही साथ देश के मजबूत चट्टानी फौलाद को भी दुश्मन देश के सामने प्रस्तुत किया। हालांकि, स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री का निधन आज भी रहस्य बना हुआ है। निधन के लगभग 59 वर्ष बाद भी इस रहस्य से पर्दा नहीं हट सका है। छोटे कद वाले मगर विशाल व्यक्तित्व के धनी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु को भले ही उस वक्त सामान्य घोषित कर दिया गया हो, मगर आज भी इसे सामान्य तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता। उस वक्त उनके परिजनों ने तो हत्या की बात तक कह दी थी।

हालांकि, जितनी मुंह उतनी बातें। लाल बहादुर शास्त्री के निधन को लेकर तरह-तरह की बातें कही जाती हैं। दरअसल, पाकिस्तान के साथ 1965 की जंग को खत्म करने के मकसद से एक समझौता पत्र हस्ताक्षर करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद गए हुए थे। समझौते के महज 12 घंटे के बाद 11 जनवरी की मध्य रात्रि में 1:32 पर उनकी अचानक मौत हो जाती है। शास्त्री जी की मौत ने पूरे देश को शोक में डाल दिया था। लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी ललिता शास्त्री ने दावा किया था कि उनके पति को जहर देकर मारा गया है। इतना ही नहीं, उनके बेटे सुनील शास्त्री ने सवाल उठाया था कि उनके पिता का शरीर नीला क्यों था?

कहा तो यह भी जाता है कि समझौते को लेकर शास्त्री जी खुश नहीं थे। वह परेशान होकर अपने कमरे में टहलते हुए देखे गए थे। उस रात वह काफी असहज दिखाई दे रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री के साथ उनके सूचना अधिकारी कुलदीप नैयर भी ताशकंद में थे। कुलदीप नैयर ने भी शास्त्री जी की मौत को लेकर शक व्यक्त किया था। हैरान करने वाली बात यह भी है कि भारत सरकार ने शास्त्री जी की मौत पर जांच के लिए जिस समिति का गठन किया था, उसमें उनके निजी डॉक्टर रहे आरएन सिंह और निजी सहायक रामनाथ की भी अलग-अलग हादसों में मौत हो गई। यह दोनों लोग शास्त्री जी के साथ ताशकंद में मौजूद थे। यही कारण है कि शास्त्री जी की मौत को लेकर आशंकाएं लगातार जताई जाती है।

वह लाल बहादुर शास्त्री ही थे जिनकी प्रेरणा से भारत की सेना लाहौर के करीब पहुंच गई थी। मगर अमेरिका तथा रूस की हस्तक्षेप के बाद युद्ध को रोकना पड़ा था। शास्त्री जी ने तब जय जवान जय किसान का नारा दिया था। एक बात यह भी है कि लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनीं। इंदिरा गांधी चाहती थीं कि लाल बहादुर शास्त्री का अंतिम संस्कार उनके घरेलू शहर इलाहाबाद में हो। हालांकि, लाल बहादुर शास्त्री का परिवार इसके लिए तैयार नहीं था। शास्त्री का अंतिम संस्कार दिल्ली में किए जाने की मांग को लेकर इंदिरा गांधी के रवैये से नाराज लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी ललिता शास्त्री ने आमरण अनशन करने की धमकी दे दी थी।

आखिर क्या है ट्रंप का ग्रेटर अमेरिका का प्लान

अभिनय आकाश

भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य का जीवन अनेकोनेक इच्छाओं और लालसाओ से भरा होता है, एक के बाद एक इच्छाएं जन्म लेती रहती है। इच्छा का प्रतिबिंब भावना है। प्रबल इच्छा भावना बन कर बहती है और मनुष्य इच्छा के कारण कर्म की दिशा में कदम रख देता है, इच्छा के कारण ही मनुष्य क्रियाशील होता है । जैसी इच्छाएं होती है भावनाएं भी प्रबल और बलवान होती चली जाती है। इन्हीं इच्छाओं को लिए विश्वभर के दिग्गज नेता इतिहास को वापस लाने, इतिहास को पहले जैसा बनाने या फिर नया इतिहास लिखने की कोशिश में लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ग्रेटर अमेरिका प्लान हो या व्लादिमीर पुतिन का सोवियत संघ को फिर से जोड़ने की कोशिश। वहीं विकासशील देश भारत में भी समय समय पर अखंड भारत की मांग जोर पकड़ती रही है। ऐसे में आज आपको अमेरिका से लेकर रूस तक के विस्तार की कहानी बताएंगे और साथ ही जानेंगे कि अगर पश्चिमी देश इस तर्ज पर अपने गौरवशाली अतीत को वापस लाने की होड़ में लगे हैं तो भारत भी अपना अखंड भारत वाला सपना क्यों नहीं पूरा कर सकता है?

20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाया। लेकिन अब वो ग्रेट अमेरिका और ग्रेटर अमेरिका का ख्वाब देख रहे हैं। जिसमें कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाना शामिल है। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही ट्रंप ने एक बार फिर से अमेरिका को ग्रेटर अमेरिका बनाने का मिशन दोहरा दिया। इस बार ट्रंप ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि कनाडा में मौजूद कई लोग अपने देश को अमेरिका के 51वें राज्य के रूप में देखना चाहते हैं। अगर कनाडा अमेरिका में शामिल होता है तो कोई टैरिफ नहीं देना होगा। टैक्स बहुत कम हो जाएंगे और देश के नागरिक रूस और चीन के जहाजों के खतरों से पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। यानी ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका में शामिल होने का खुला ऑफर दे दिया है।

क्रिसमस से ठीक पहले ट्रंप के बेटे एरिक ने एक तस्वीर पोस्ट की थी। एक शॉपिंग कार्ट को डोनाल्ड ट्रंप अपने मोबाइल पर देख रहे हैं। इसमें सबसे ऊपर कनाडा नजर आया, बीच में ग्रीनलैंड और उसके नीचे पनामा कनाल नजर आ रहा था। ट्रंप कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाना चाहते हैं। वो ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करना चाहते हैं। इसके साथ ही वो पनामा नहर पर कब्जा करना चाहता है।

साल 2018 की बात है एक पत्रकार ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पूछा कि आप अपने देश के इतिहास में किस घटनाक्रम को पलटना चाहोगे। पुतिन ने एक लाइन में बोला- द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन। कई मौके ऐसे आए जब पुतिन ने साफगोई से कहा कि अगर वो ऐसा कर सकते तो यूएसएसआर के विघटन की कहानी को उलट कर रख देते। कुछ ऐसा ही रूसी राष्ट्रपति करते भी नजर आ रहे हैं। इतिहास को पलटने, पुराना इतिहास वापस लाने या फिर कहे कि एक नया ही इतिहास लिखने की कोशिश में रूसी राष्ट्रपति नजर आ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बिना एक भी गोली चलाए यूक्रेन को तीन हिस्सों में बांट दिया। 2008 में जॉर्जिया, 2014 में क्रीमिया, 8 साल बाद यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी और तीन सालों से जंग जारी है।

सोवियत संघ के बनने और बिखड़ने की 70 साल की इस कहानी में ऐसे कई मुकाम आए थे जब दुनिया इसकी ताकत के सामने हिल गई थी। साल 1917 में जब यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में फैले देश रूस के शासक जार के कुशासन के खिलाफ लेनिन ने बोल्सेविक क्रांति का बिगुल बजाया था। लेनिन मार्क्सवाद से प्रेरित थे और इसी के आधार पर उन्होंने रूसी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की और जार की सत्ता को उखाड़ फेंका और सोवियत संघ की स्थापना की। इस संघ में रूस की सीमा से लगे एशिया और यूरोप के कई इलाके शामिल थे। जिन्हें आज दुनिया बेलारूस, आर्मीनिया, अजरबैजान, इस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, कीर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मालदोवा, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज़्बेकिस्तान जैसे देशों के नाम से जानती है।

पहले के समय में भारत 16 जनपदों में बंटा हुआ था। आज तो ये सभी जानते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान तो भारत से ही अलग हुए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इनको मिलाकर करीब 20 से भी ज्यादा देश भारत से अलग हो चुके हैं। 25 सौ साल पहले भारत अखंड हुआ करता था। लेकिन अरब, तुर्क, शक्य, फूल, कुशल, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसि और अंग्रेजों ने मिलकर भारत के कई टुकड़े कर दिए।

अखंड भारत का अर्थ है अविभाजित भारत जिसका भौगोलिक विस्तार प्राचीन काल में बहुत विस्तृत था और इसमें वर्तमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाइलैंड शामिल थे। अखंड भारत का विचार सनातन भारतीय सभ्यता जितना ही पुराना है क्योंकि इसे प्राचीन भारतीय शास्त्रों में विधिवत स्थान मिला। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, वर्तमान के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आधुनिक भारत, नेपाल, बर्मा, तिब्बत, भूटान और बांग्लादेश के आधुनिक राष्ट्रों को भारतीय उपमहाद्वीप कवर करता था। बाद में कई स्वतंत्र राज्यों में विभाजित किया गया था। ऋषियों के आश्रम में पले और युगपुरुषों की उंगली थाम कर चले वाले अखंड भारत की कहानी अपने आप में बहुत ही दिलचस्प रही है। इतिहास का पहला पन्ना तब लिखा गया था जब मनुष्यों ने दिन को समय और तारीखों में बांटना नहीं सीखा था। आज मानचित्र में जैसी छवि है भारत हमेशा से ऐसा नहीं था।

दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हालांकि ये बेहद मुश्किल जरूर है। सभी देश आज आजाद हैं और उनका अपना संविधान है। अपनी राजनीतिक व्यवस्था है। इन्हें वापस जोड़ने के दो रास्ते हैं। पहला ये कि जंग करके भारत इन पर कब्जा कर ले। जिसकी फिलहाल कोई संभावना नहीं है। दूसरा ये कि ये देश खुद ही अपनी मर्जी से अखंड भारत में शामिल हो जाए। लेकिन इसके अलावा तीसरा विकल्प ये भी है कि ईयू कि तर्ज पर ऐसा गठबंधन बने। एक यूनियन हो और उसका एक पार्लियामेंट हो जहां सभी देश मिलकर बिल पास करे और उस पर एक्शन ले। अभी हमारे पास क्यू ऑपरेशन के नाम पर केवल शार्क समिट है। लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि हर साल इसका महत्व और घटता ही जा रहा है। अखंड भारत के प्लान में एक बड़ा फायदा अर्थव्यवस्था को भी पहुंचेगा। इससे सभी देश ट्रेड करना आसान हो जाएगा।

आज का इतिहास

1922 डायबटीज के मरीजों को पहली इंसुलिन दी गई।
1923 फ्रांस और बेल्जियम के सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जर्मन वीमार गणराज्य को मजबूर करने के लिए रुहर क्षेत्र पर आक्रमण किया।
1946 अल्बानिया की पार्टी ऑफ लेबर के पहले सचिव एनवर होक्सा ने खुद के साथ पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया घोषित किया।
1949 लॉसएंजिल्स में सबसे ज्यादा हिमपात होने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया।
1954 बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज उठाने वाले नोबल विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म हुआ।
1962 पेरू के उत्तर पश्चिम हिस्से में बर्फीले तूफान और चट्टान खिसकने से 2,000 लोगों की मौत हुई।
1972 पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र देश बना।
1986 ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में गेटवे ब्रिज, उस समय दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाले कंक्रीट मुक्त-कैंटिलीवर पुल को खोला गया था।
1992 सांस्कृतिक बहिष्कार के अंत के बाद गायक पॉल साइमन दक्षिण अफ्रीका का दौरा करने वाला पहला प्रमुख कलाकार था।
1998 टिम एलन सीनफील्ड में 24 वें वार्षिक पीपुल्स च्वाइस अवार्ड्स जीते।
1998 76 प्रदर्शनों के बाद प्रस्ताव न्यूयॉर्क शहर के ब्रॉडहर्स्ट थियेटर में बंद हो गया।
2007 2007 में, 11 जनवरी को वियतनाम विश्व व्यापार संगठन का 150 वां सदस्य बना।
2008 माउन्ट एवरेस्ट के प्रथम आरोहनकर्ता और समाजसेवी सर एडमंड हिलारी का निधन हुआ।
2009 66वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में स्लमडॉग मिलियनेयर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला।
2012 इज़रायल के सैन्य प्रमुख के अनुसार इज़राइल गोलान हाइट्स में सीरियाई शरणार्थियों की वृद्धि की तैयारी कर रहा है।
2012 सीरिया के हॉर्न में आठ अन्य मोटर्स के साथ एक पत्रकार की हत्या कर दी गई।

आखिर चुनावी रेवड़ी को परिभाषित करना इतना मुश्किल क्यों है?

कमलेश पांडेय

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा करते वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि %चुनावी रेवड़ी% क्या है, इसे परिभाषित करना मुश्किल है। चूंकि इस मुद्दे पर आयोग के हाथ बंधे हुए हैं। इसलिए, कानूनी उत्तर ढूंढे जाएं। हालांकि, उनकी इस साफगोई से हमारी संसद और हमारे संविधान के संरक्षक सुप्रीम कोर्ट, दोनों की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। वह यह कि वो जल्द से जल्द इस मसले पर व्याप्त कानूनी असमंजस को दूर करने के लिए एक नेक पहल करें।

वहीं, अब तक ऐसा नहीं होना निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया पर एक गम्भीर सवालिया निशान छोड़ जाता है। क्योंकि जब इस मसले पर स्पष्ट नियमन होंगे तो इसका उल्लंघन करने वाले राजनीतिक दलों व उनके नेताओं को कानून के कठघरे में खड़ा किया जा सकेगा। हालांकि, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की बात से अब यह स्पष्ट हो चुका है कि आजादी और गणतंत्र बनने के इतने दशकों बाद भी हमारे सत्ता पक्ष या विपक्ष ने कभी इस मुद्दे पर स्पष्ट नियमन बनाने की पहल ही नहीं की, ताकि दुविधाजनक कानूनी परिस्थितियों से चुनावी लाभ उठाते रहा जाए।

जबकि, मीडिया में इस बारे में जब-तब बहस होती रहती है, और सर्वोच्च न्यायालय में भी इस बारे में कुछ जनहित दायर है, जिस पर दो टूक निर्णय की प्रतीक्षा देशवासियों को है। लेकिन वर्ष 2018 से अब तक इस पर स्पष्ट निर्णय नहीं हो पाया है। यह गम्भीर बात है, क्योंकि इससे इस अहम मसले पर राजनेताओं और सम्बन्धित पेशेवरों द्वारा जितने मुंह, उतनी बातें की जा रही हैं जिससे मतदाता भी असमंजस में हैं। इसके उलट जिन्हें फ्रीबीज यानी मुफ्त की चुनावी रेवड़ी का लाभ मिल रहा है, उनकी तो बल्ले बल्ले है। वहीं, जिन करदाताओं की जेबें तरह-तरह के टैक्स के माध्यम से हर रोज काटी जा रही हैं और सरकार प्रदत्त जनसुविधा भी नदारत या नाकाफी दिख रहीं हैं, उनके दिलोदिमाग में इस सियासी प्रवृत्ति को लेकर अनेक सवाल उठ रहे हैं।

वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी गत दिनों फ्रीबीज मामले पर सख्त टिप्पणी की और कहा कि राज्यों के पास उन लोगों को 'मुफ्त सौगात' देने के लिए पर्याप्त धन है, जो कोई काम नहीं करते। लेकिन जजों की सैलरी-पेंशन देने के लिए नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्य के पास मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए पैसे हैं, लेकिन जजों की सैलरी-पेंशन देने के लिए नहीं है। राज्य सरकारों के पास उन लोगों के लिए पूरा पैसा है, जो कुछ नहीं करते; लेकिन जब जजों की सैलरी की बात आती है तो वे वित्तीय संकट का बहाना बनाते हैं।

बता दें कि जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह मौखिक टिप्पणी उस समय की, जब अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ से जुड़ी एक याचिका के निपटारे के क्रम में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने दलील दी कि सरकार को न्यायिक अधिकारियों के वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों पर निर्णय लेते समय वित्तीय बाधाओं पर विचार करना होगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की कि, राज्य के पास उन लोगों के लिए पैसा है जो कोई काम नहीं करते। चुनाव आते हैं, आप लाडली बहना और अन्य नयी योजनाएं घोषित करते हैं, जिसके तहत आप निश्चित राशि का भुगतान करते हैं। दिल्ली में अब आए दिन कोई न कोई पार्टी घोषणा कर रही है कि वे सत्ता में आने पर 2,500 रुपये देंगे।

उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत ने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पेंशन के संबंध में अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ की ओर से 2015 में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। जबकि, अटार्नी जरनल आर वेंकटरमणि ने कहा कि वित्तीय बोझ की वास्तविक चिंताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि, यह 'दयनीय' है कि उच्च न्यायालय के कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को 10,000 रुपये से 15,000 रुपये के बीच पेंशन मिल रही है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है, जब दिल्ली चुनाव में फ्रीबीज की बहार है। आम आदमी पार्टी ने वादा किया है कि उसकी सरकार बनी तो महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने मिलेंगे। जबकि कांग्रेस 2500 रुपए देने की बात कह रही है। वहीं, भाजपा भी इसी तरह का ऐलान जल्द करने वाली है।

उधर, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही पूरे दिल्ली में रेवड़ी पर चर्चा अभियान की शुरूआत कर दी थी। इस मौके पर उन्होंने दो टूक कहा था कि जनता का पैसा, जनता की रेवड़ी, तो उस पर हक़ भी जनता का ही है। केजरीवाल ने कहा कि, %पीएम मोदी ने कई बार कहा है कि केजरीवाल मुफ़्त की रेवड़ी दे रहे हैं और इसे बंद किया जाना चाहिए। जबकि केजरीवाल खुलेआम कह रहा है कि हम ये रेवड़ी दे रहे हैं। अब दिल्ली के लोगों को तय करना है कि उन्हें ये रेवड़ी चाहिए या नहीं। उन्होंने आगे चेताया कि, अगर बीजेपी जीतती है तो वे ये योजनाएं बंद कर देगी। क्योंकि बीजेपी ने अपने और अपने गठबंधन द्वारा शासित राज्यों में ये रेवड़ियां लागू नहीं की हैं। हालांकि उसकी कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने दो टूक कहा कि, ये मुफ़्त की रेवड़ी नहीं हैं बल्कि ये करदाताओं के पैसे से लागू की गई योजनाएं

हैं।

वहीं, चुनाव आयोग ने भी इस मुद्दे पर कहा था कि, जिसे आप सामान्य भाषा में फ्रीबीज़ यानी मुफ़्त की चीज़ें कह रहे हैं, वे महामारी जैसे दौर में लोगों की जान बचा सकती हैं। हो सकता है एक वर्ग के लिए जो अतार्किक हो वो दूसरे वर्ग के लिए ज़रूरी हो।

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक पार्टियों और मुफ़्त में सुविधाएं दिए जाने का ज़िक्र करते हुए एक बार कहा था कि, इस तरह के वादे करके वोटरों को लुभाना राष्ट्र निर्माण नहीं, बल्कि राष्ट्र को पीछे धकेलने की कोशिश है। अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल-डीज़ल भी मुफ़्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे क़दम हमारे बच्चों से उनका हक़ छीनेंगे। देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। ऐसी स्वार्थभरी नीतियों से देश के ईमानदार करदाता का बोझ भी बढ़ता ही जाएगा। ये नीति नहीं %अनीति% है। ये राष्ट्रहित नहीं, ये राष्ट्र का अहित है।

एक बार पीएम मोदी ने बुंदेलखंड-एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए उत्तर प्रदेश के जालौन में तो यहां तक कह दिया था कि, आजकल हमारे देश में मुफ़्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ़्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें ख़रीद लेंगे। हमें मिलकर रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है।

वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि, कहा जा रहा है कि अगर सरकारें जनता को फ्री में सुविधाएं देंगी तो सरकारें कंगाल हो जाएंगी। देश के लिए बहुत आफ़त पैदा हो जाएगी। इन सारी फ्री की सुविधाओं को बंद किया जाए। इससे मन में एक शक पैदा होता है कि कहीं केंद्र सरकार की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा खराब तो नहीं हो गयी है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन सारी चीजों को बंद करने, वापस लेने या इनका विरोध करने की स्थिति आ गई। इससे दो कदम आगे बढ़कर उन्होंने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने करोड़पति उद्योगपतियों के दस लाख करोड़ रुपए के कर्ज़ माफ़ किए थे। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा था कि, जब 2014 में केंद्र सरकार का बीस लाख करोड़ का बजट होता था। और आज केंद्र सरकार का बजट लगभग चालीस लाख करोड़ का है तो ये सारा पैसा जा कहां रहा है। इन्होंने बहुत अमीर लोग जो अरबपति हैं, उनके दस लाख करोड़ रुपये के कर्ज़े माफ कर दिए। अगर ये हज़ारों लाखों करोड़ों रुपये के कर्ज़े माफ़ नहीं किए जाते तो इन्हें खाने-पीने की चीज़ों पर टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि एक बार कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल का जवाब ट्वीट किया था। जिसके अनुसार 2017 से लेकर 2022 के बीच बैंकों ने क़रीब 10 लाख करोड़ रुपये के कर्ज़ माफ़ किए हैं। तब उनका कहना था कि सरकार मध्यवर्ग के करदाताओं को लूट रही है। लिहाजा इसी का ज़िक्र अरविंद केजरीवाल ने भी किया था, जो सही है।

वहीं, चुनाव अभियानों में राजनीतिक पार्टियों के मुफ़्त चीज़ें और पैसे देने के वादों से संबंधित एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे %एक गंभीर मुद्दा% बताया है। वर्ष 2022 में ही एक याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्कालीन चीफ़ जस्टिस एनवी रमन्ना और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने कहा था कि- ये एक गंभीर मुद्दा है। जिन्हें ये मिल रहा है वो ज़रूरतमंद हैं और हम वेलफ़ेयर स्टेट हैं। कुछ टैक्सपेयर कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल विकास के लिए किया जाए। इसलिए ये गंभीर मुद्दा है। अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान और वेलफ़ेयर में बैलेंस की ज़रूरत है। दोनों ही पक्षों को सुना जाना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि इस बाबत जनहित याचिका दायर करने वाले बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने गुज़ारिश की है कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों के चुनावी घोषणापत्र को नियंत्रित करने और उनके वादों के लिए उन्हें ज़िम्मेदार ठहराने से जुड़ा क़ानून लाए और बिना सोच समझकर अतार्किक वादे करने वाली पार्टियों को बैन करे। उनका कहना है कि मुफ़्त चीज़ों की घोषणा करते वक़्त राजनीतिक पार्टियां सरकार पर पड़ रहे कर्ज़ के बोझ का ध्यान रखें और बताएं कि इसके लिए पैसा किसकी जेब से आ रहा है।

इस बारे में अश्विनी उपाध्याय ने बताया था कि, हमने कोर्ट से यही कहा है कि इस समय केंद्र और राज्य सरकारों पर 150 लाख करोड़ रुपये का कर्ज़ हो चुका है। अगर इसे नहीं रोका गया तो आने वाले समय में स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। हमें न विश्व बैंक, न अमेरिका, न जापान कर्ज़ देगा। स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जाएगी। केंद्र सरकार ने भी हमारी जनहित याचिका का समर्थन किया है और कहा है कि जन कल्याणकारी योजनाएं तो चलनी चाहिए लेकिन मुफ़्तखोरी की योजनाएं बंद होनी चाहिए। हमने अपनी ओर से सात सदस्यों की एक समिति का प्रस्ताव दिया है। यह समिति बताए कि मुफ़्तखोरी को कैसे रोका जाए और राज्यों पर जो कर्ज़ बढ़ रहा है, उसे कैसे कम किया जाए।

यूँ तो भारत में इससे पहले भी सब्सिडी के मुद्दे पर विचार-विमर्श होता रहा है। सब्सिडी के औचित्य आदि पर गंभीर चर्चाएं हुई हैं। लेकिन इस मुद्दे पर इस तरह राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप ने नए सुलगते हुए सवाल खड़े किए हैं। वह यह कि क्या मुफ़्त में चीजें या सेवाएं देना उचित है? क्योंकि राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए मुफ़्त में चीज़ें या सुविधाएं देने का वादा हमेशा से करती रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये किया जाना उचित है?

इस विषय पर राजनीतिक मामलों के जानकार बताते हैं कि जब आप वोट मांगने जाते हैं तो इस तरह की बातें कहनी होती हैं। लेकिन इसमें एक फ़र्क है कि सामान्य रूप से ये कहना कि हम सबका ध्यान रखेंगे और स्पेसिफिक रूप से कहना जैसे %15 लाख आएंगे और हम सबको दे देंगे।% उन्हें लगता है कि इस तरह स्पेसिफिक वादे करना ग़लत होता है। ये कहना भी ग़लत है कि हम जब आएंगे तो बिजली के बिल में दो या तीन रुपये माफ़ कर देंगे या बिलकुल ही ख़त्म कर देंगे। दरअसल, ये प्रवृत्ति किसी एक दल की नहीं है, बल्कि सभी दलों की होती है लेकिन ये प्रवृत्ति रुकनी चाहिए। अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी नियम कानून होने चाहिए कि उसे किस तरह होना चाहिए। इसकी जवाबदेही भी होनी चाहिए।

लेकिन क्या जन कल्याणकारी योजनाओं और हाल ही में सामने आए टर्म %मुफ़्त की रेवड़ी% को एक तरह देखा जा सकता है? इस सवाल पर जानकार बताते हैं कि एक ऐसा समाज जहां आर्थिक और सामाजिक समेत तमाम तरह की विषमताएं हैं। वहां सभी के लिए एक जैसा कदम नहीं उठाया जा सकता। ऐसे में वंचितों और शोषितों का कल्याण करना हर सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में अगर आपका काम बहुसंख्यक समाज को लाभांवित नहीं करेगा तो आप चुनकर नहीं आ सकते। ऐसे में ये कहा जाए है कि हमारी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगी। यहां तक तो ठीक है। लेकिन धीरे-धीरे ये होने लगा है कि जनता से वादे करो और फिर भूल जाओ। ऐसे में पहले जो एक फुंसी थी, उसने अब कैंसर का रूप ले लिया है। इस प्रवृत्ति का नतीजा ये हुआ कि कहा जाने लगा कि हम फ्री बिजली देंगे। पानी देंगे। गैस देंगे, आदि आदि। बताइए कि कोई भी सरकार फ्री बिजली कैसे दे सकती है। आख़िरकार पैसा टैक्सपेयर का है। और फ्री बिजली सबको क्यों मिलनी चाहिए...जो लोग बिजली ख़रीद सकते हैं, उन्हें फ्री में क्यों मिलनी चाहिए।

पाकिस्तान को बड़ा झटका देने की तैयारी में अमेरिका

नितिन गौतम

पाकिस्तान एक तरफ आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और दूसरी तरफ अफगान तालिबान ने उसकी नाक में दम किया हुआ है। अब अमेरिका भी पाकिस्तान को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है। दरअसल अमेरिकी संसद में एक सांसद ने विधेयक पेश किया है, जिसमें पाकिस्तान का गैर नाटो सहयोगी का दर्जा खत्म करने का प्रस्ताव किया गया है।

एक प्रभावशाली रिपब्लिकन सांसद एंडी बिग्स ने संसद में विधेयक पेश किया है। इस विधेयक में कहा गया है कि राष्ट्रपति को तब तक पाकिस्तान को गैर नाटो सहयोगी का दर्जा देने वाला प्रमाणपत्र जारी नहीं करना चाहिए, जब तक पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी नहीं रखता है। विधेयक में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान को हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान की धरती पर रहकर अपनी गतिविधियां चलाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। साथ ही पाकिस्तान को अफगान सरकार के साथ मिलकर हक्कानी नेटवर्क की मूवमेंट को बाधित करने के लिए भी कहा जाना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि साल 2004 में अमेरिका ने अल-कायदा और तालिबान से लड़ने के लिए पाकिस्तान को गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया था। इसके तहत पाकिस्तान को अमेरिका से हथियार, हथियार बिक्री प्रक्रिया में छूट और ऋण कार्यक्रम में भी प्राथमिकता मिलती रही है। इस दर्जे के तहत पाकिस्तान, अमेरिका के आधुनिका हथियारों को भी खरीदने का पात्र है।

बीते करीब दो दशकों में अमेरिका ने इसके तहत पाकिस्तान को अरबों डॉलर की आर्थिक मदद और आधुनिक हथियार दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस मदद का इस्तेमाल आतंकवाद से लड़ने की बजाय उसे और पोषित करने और भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया है। जिस अल-कायदा से लड़ने के लिए पाकिस्तान को अरबों डॉलर मिले, उसी अल-कायदा का प्रमुख ओसामा बिल लादेन पाकिस्तान से ही पकड़ा गया था। यही वजह है कि पाकिस्तान का गैर-नाटो सहयोगी दर्जा खत्म करने की मांग हो रही है। एंडी बिग्स ने जनवरी 2019 में पहली बार यह विधेयक अमेरिकी संसद के निचले सदन में पेश किया था। हालांकि उसके बाद से यह विधेयक खास प्रगति नहीं कर सका और अभी तक संसद से पास नहीं हुआ है। अब एक बार फिर से एंडी बिग्सने यह विधेयक पेश किया है। डोनाल्ड ट्रंप साल 2020 में चुनाव हारने के बाद पहली बार गुरुवार को यूएस कैपिटल पहुंचे। ट्रंप ने यूएस कैपिटल में पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर को श्रद्धांजलि अर्पित की। चार साल बाद फिर से यूएस कैपिटल आने पर उन्होंने खुशी जाहिर की और कहा कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। इस दौरान ट्रंप ने रिपब्लिकन सांसदों से भी बंद दरवाजों के पीछे बैठकें की।

आप की लगेगी हैट्रिक या किसी और को मिलेगी जीत?

संध्या

दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होने है और 8 फरवरी को नतीजे आने हैं। चुनाव तारीखों के एलान के साथ ही राजधानी में सियासी हलचल बढ़ गई है। पार्टियां हर सीट के हिसाब अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं। इस चुनाव में कुछ ऐसी सीटें हैं जिनकी बात अभी से की जा रही है। ओखला विधानसभा सीट भी ऐसी ही बेहद खास और चर्चित सीट है। यहां से एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह खान को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अभी तक अपने चेहरों का ऐलान नहीं किया है।

ओखला सीट पर पहला चुनाव साल 1977 में हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस और जनता पार्टी का मुकाबला हुआ। नतीजा जनता पार्टी के टिकट पर उतरे ललित मोहन गौतम के पक्ष में रहा। उन्होंने कांग्रेस के दीवान द्वारका खोसला को 5098 मत से शिकस्त दी थी। 1983 के चुनाव में ओखला में कांग्रेस और

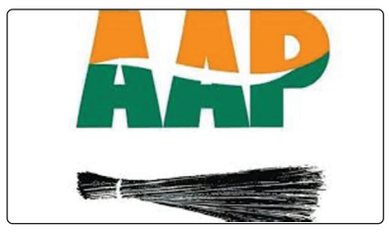

भाजपा के बीच में हुआ। कांग्रेस उम्मीदवार देसराज छाबड़ा ने भाजपा के रतन सिंह को महज 800 वोट से हराया था।

दिल्ली के विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 1993 में फिर से विधानसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में ओखला सीट पर जनता दल ने सफलता हासिल की। पार्टी की तरफ से उतरे परवेज हाशमी ने कांग्रेस नेता हसन अहमद को 1307 वोट से हराया था।

साल 1998 में हुए विधानसभा चुनाव में ओखला का नतीजा फिर परवेज हाशमी के पक्ष में रहा लेकिन इस बार दल अलग था। परवेज इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में उतरे परवेज ने भाजपा के कृष्ण कुमार मेहता को 18161 वोट से शिकस्त दी। परवेज हाशमी बाद में दिल्ली से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भी बने।

2020 के विधानसभा चुनाव में आप आदमी पार्टी ने फिर जबरदस्त जनादेश हासिल किया। आप को 70 में से कुल 62 सीटों पर जीत मिली। ओखला के नतीजों की बात करें तो यहां से आप की तरफ से प्रमुख नेता अमानतुल्लाह खान को फिर एक बड़ी जीत मिली। आप नेता अमानतुल्लाह ने भाजपा के ब्रह्म सिंह को 71827 वोट से पटखनी दी थी। आप को 130367 वोट जबकि दूसरे नंबर पर रही भाजपा को 58540 वोट मिले।

2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने ओखला सीट से विधायक अमानतुल्लाह खान को ओखला से टिकट दिया है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने यहां अभी अपने उम्मीदवार नहीं तय किए हैं।

नए चीनी वायरस से दहशत

डॉ. रमेश ठाकुर

चाइना की धरती से निकलकर दुनिया में कोहराम मचाने वाले जानलेवा वायरस बेकसूर इंसानों का पीछा करना कभी छोड़ेंगे या नहीं? क्योंकि प्रत्येक खतरनाक वायरसों का केंद्र चीन ही होता है? कोविड-19 के बाद एक ऐसी अबूझ पहेली है जिसे न डब्ल्यूएचओ सुलझा पाया और न ही दुनिया की तमाम चिकित्सा रिसर्च रिपोर्ट किसी नतीजे पर पहुंच पाईं? हालांकि, वायरस के निमार्ण के पीछे चीनी हिमाकत पर शक तो सभी को बहुत पहले से है? लेकिन तथ्यों के साथ कोई उसे एक्सपोज नहीं कर पाया? ऐसे अंसख्यक सवाल हैं जो उनके इस नए 'ह्यूमन मेटान्यूमो' वायरस यानी एचएमपीवी के बाद खड़े हुए हैं। सवाल दरअसल खड़े होने भी चाहिए, आखिर क्यों लोगों की जान लेने पर वो आमादा है। वायरसों के इतर भी उनकी अमानवीय नापाक हरकतों से न सिर्फ पड़ोसी मुल्क, बल्कि समूचा संसार परेशान और दुखी हुआ पड़ा है। ऐसे में विश्व बिरादरी को सामूहिक रूप से 'ह्यूमन मेटान्यूमो' वायरस की तथ्यों सहित तहकीकात करके जानकारी को सार्वजनिक करना चाहिए। हालांकि, चीन नए वायरस के आरोपों को नकार रहा है।

गौरतलब है बीते 3 वर्ष पूर्व कोरोना वायरस ने संसार को जो गहरे जख्म दिए थे, वो आज भी हरे हैं और तब तक रहेंगे? शायद जब तक इस धरती पर इंसानों का वजूद रहेगा? क्योंकि कोरोनाकाल में कोई परिवार ऐसा नहीं बचा होगा जिसने अपने किसी सगे या कोई करीबी दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार को न खोया हो? भारत में 'ह्यूमन

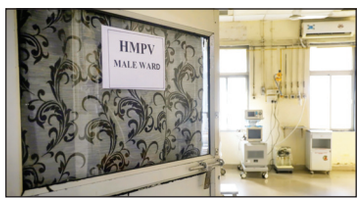

मेटान्यूमो' का पहला संक्रमण एक बच्ची में 6 जनवरी को सुबह कर्नाटक में मिला और शाम होते-होते गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक मरीजों की संख्या पांच-छह तक पहुंच गई। संक्रमितों की खबर ने ऐसी दहशत फैलाई, जिससे केंद्र सरकार भी हलकान हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को भी मीडिया में आकर बताना पड़ा, कि देशवासियों को फिलहाल चिंता करने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि स्थिति पर उनका पूर्ण नियंत्रण है और संपूर्ण इंतजाम केंद्रीय स्तर पर किए जा चुके हैं। उन्होंने इस वायरस को नया नहीं, बल्कि पुराना ही बताया है? जबकि, आइसीएमआर का मानना है कि सर्दियों में सामान्य न्यूमोनिया वायरसों का खतरा हमेशा बढ़ता है। पर, ये वायरस जानलेवा कभी नहीं होते थे, लेकिन अब होने लगे हैं।

'ह्यूमन मेटान्यूमो' वायरस पर हेल्थ मिनिस्ट्र और आइसीएमआर दोनों के बयानां में अंतर है। बिना तालमेल और अ-पुष्ट सूचनाओं के आदान-प्रदान से सभी को बचना होगा। क्योंकि इससे स्थिति बिलावजह नाजुक हो जाती हैं। दोनों संस्थाओं को सबसे पहले मॉनिटरिंग पर फोकस करना होगा, जो कोरोना के वक्त अच्छे से नहीं किया था। नए वायरस की जागरूकता पर दोनों की माने तो खतरा है भी, और नहीं भी? हालांकि इसके बाद गेंद जनता के पाले में चली जाती है। कहने का मतलब है, सतर्कता जनता को स्वयं से करनी होगी। उन्हें अपनी इम्युनिटी पर खासा ध्यान रखना होगा। क्योंकि कोरोना के वक्त भी हुकूमत और चिकित्सीय संगठनों की ओर से शुरुआत में कुछ ऐसा ही कहा गया था। लेकिन उसके बाद में हालात कैसे बनें, जिसे बयां करने मात्र से आज भी रूहें कांप उठती हैं। पूरे सिक्किम राज्य की जितनी मौजूदा समय में आबादी है, उससे कहीं ज्यादा भारतीयों की जाने कोरोना से गईं। 'ह्यूमन मेटान्यूमो' को लेकर आमजन को इसलिए चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वायरस की भी अभी तक कोई टीका या एंटीवायरल दवा नहीं निर्मित हुई है। भारत में 'ह्यूमन मेटान्यूमो' के अभी तक जितने केस सामने आए हैं उन सभी मरीजों को सामान्य बुखार की दवाइयां ही दी जा रही हैं। किसी विशेष दवा का प्रबंध भी नहीं हुआ है।

गौरतलब है कि डब्ल्यूएचओ ने चीन से 'ह्यूमन मेटान्यूमो' वायरस को लेकर रिपोर्ट मांगी है, जिसे उसने अभी तक नहीं दी? इससे तो यह कहावत सीधे-सीधे चरितार्थ होती है कि 'चोर की दाढ़ी में तिनका'। चीन की चालाकी को लेकर न सिर्फ भारत को, बल्कि पूरे संसार को चौकन्ना रहना होगा। क्योंकि वायरस के खेल के पीछे उसकी विश्वसनीयता कोरोना के बाद भयंकर रूप से सवालों के घेरे में आ चुकी है। अब देखिए न, डब्ल्यूएचओ के बार-बार मांगने पर भी चीन ने डाटा रिपोर्ट नहीं मुहैया करवाई है। इससे संदेह न हो, तो और क्या? नए वायरस से बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं को विशेष पर बचना होगा। उनके लिए घातक ये वायरस। इसके अलावा कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों, जैसे दिल, फेफड़े, लिवर, कैंसर, चर्म रोगियों को और भी ज्यादा सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। वायरस को लेकर समूचे विश्व में फिलहाल भ्रम की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली स्थित 'एम्स' अस्पताल की तत्कालीक चिकित्सा शोध रिपोर्ट 'ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस' की उत्पत्ति सन-2001 में होना दर्शाती है जिसमें मात्र श्वसन संक्रमण का ही खतरा रहता है और ज्यादा कुछ नहीं? पर, वायरस के इस नए वर्जन से मरीजों के हताहत होने की सूचनाएं हैं। संदेह दरअसल यहीं से गहरा जाता हैं कि कहीं इस पुराने वायरस की आड़ में कोई नया मानव निर्मित वायरस तो नहीं फैलाया गया है?

बहरहाल, 'ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस' को लेकर भ्रम की स्थिति यहीं से पता चलती है, कि दुनिया के कई देश इस वायरस को जहां रहस्यमय कह रहे हैं। तो वहीं, भारतीय चिकित्सक पुराना वायरस बताने में तुले हैं। हालांकि, भारतीय को अभी हद से ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एचएमपीवी का व्यापक असर अभी चीन में भी नहीं है अन्य देशों में भी एकाध ही केस फाइल हुए हैं। ग्लोबल स्तर पर ज्यादातर देशों के मध्य एक चिकित्सीय संधी बनी होती है जिसके तहत जिस देश से कोई रहस्यमय बीमारी या वायरस फैलता है तो उसकी संपूर्ण जानकारियां डब्ल्यूएचओ जैसी विश्वस्तरीय मेडिकल संगठनों को मुहैया करानी होती है। पर, चीन एचएमपीवी को लेकर भी कुंडली मारे बैठा है।

इलॉन मस्क के यूरोपीय राजनीति में दखल से चिंतित हैं नेता

टेस्ला और स्पेसएक्स के संस्थापक इलॉन मस्क पर यूरोपीय राजनीति में हस्तक्षेप के आरोप लग रहे हैं। मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का इस्तेमाल करते हुए कई बार धुर-दक्षिणपंथी विचारधाराओं का समर्थन किया है। इस वजह से यूरोप के कई नेताओं ने उनकी आलोचना की है। उनका कहना है कि मस्क का यह रवैया लोकतांत्रिक संस्थानों और सार्वजनिक विमर्श को नुकसान पहुंचा सकता है। इलॉन मस्क के विवादास्पद बयान और हरकतों ने यूरोपीय नेताओं को असहज कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे डॉनल्ड ट्रंप को आर्थिक सहयोग देने के बाद, मस्क ने अब यूरोप का रुख किया है। उन्होंने जर्मनी की धुर-दक्षिणपंथी पार्टी ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी (एएफडी) का समर्थन किया और ब्रिटिश प्रधानमंत्री किएर स्टारमर पर तीखे हमले किए। मस्क अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धुर-दक्षिणपंथी खातों और प्रवासी विरोधी विचारों को बढ़ावा देते रहे हैं। राजनीतिक संचार के प्रोफेसर एंड्रयू चाडविक ने मस्क की तुलना पुराने जमाने के अखबार मालिकों से की। उन्होंने कहा, मस्क अपने मंच का इस्तेमाल करके दक्षिणपंथी विचारधाराओं को बढ़ावा दे रहे हैं और अपने विचार थोपने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज ने मस्क की नीतियों की कड़ी आलोचना की। फ्रांको की तानाशाही के 50 साल पूरे होने के एक कार्यक्रम में उन्होंने बिना नाम लिए मस्क को निशाना बनाया। उन्होंने कहा, दुनिया का सबसे अमीर आदमी हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों पर हमला कर रहा है और नफरत फैला रहा है। कैटालोनिया के क्षेत्रीय अध्यक्ष सल्वाडोर ईया ने भी मस्क के खिलाफ अपनी चिंता जताई। उन्होंने मस्क द्वारा कैटालोनिया में प्रवासियों से जुड़े एक लेख को रीट्वीट करने पर कहा कि हमें एक ऐसे टेक अरबपति के हाथों में नहीं पड़ना चाहिए, जो दक्षिणपंथी विचारधारा का समर्थक है। जर्मनी में भी मस्क के बयान चर्चा का विषय बने हैं। चांसलर ओलाफ शोल्त्स की सरकार के गिरने के बाद फरवरी में होने वाले चुनावों से पहले मस्क ने एएफडी का समर्थन किया। उन्होंने एक पोस्ट में जर्मनी को आर्थिक और सांस्कृतिक पतन के कगार पर बताया। शोल्त्स ने इस पर जवाब देते हुए कहा, जर्मनी का भविष्य सोशल मीडिया मालिक तय नहीं करेंगे, बल्कि जनता करेगी। ब्रिटेन में मस्क ने प्रधानमंत्री किएर स्टारमर पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने स्टारमर को दुष्ट तानाशाह कहा और उन पर पुराने बाल यौन शोषण मामलों में मिलीभगत का आरोप लगाया। स्टारमर ने इन आरोपों को झूठ और भ्रामक बताया। इस विवाद के बाद ब्रिटेन में विदेशी हस्तक्षेप रोकने के लिए सख्त कानूनों की मांग तेज हो गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों और ग्रीस के स्वास्थ्य मंत्री एडोनिस जॉर्जियाडिस ने भी मस्क के रवैये की आलोचना की है। माक्रों ने कहा कि टेक अरबपतियों का यह हस्तक्षेप लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। जॉर्जियाडिस ने मस्क के व्यवहार को चिंताजनक और गैर-जिम्मेदाराना बताया। मस्क के यूरोपीय राजनीति में हस्तक्षेप से यह साफ दिखता है कि वह दक्षिणपंथी विचारधाराओं के करीब हैं। उनकी प्रवासी विरोधी टिप्पणियां और प्रगतिशील नेताओं पर हमले यह दर्शाते हैं कि वह सार्वजनिक चर्चा और राजनीति को अपने अनुसार मोड़ना चाहते हैं। उनके समर्थक इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताते हैं, लेकिन आलोचकों का मानना है कि वह अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर रहे हैं। यूरोपीय संघ (ईयू) ने अपने डिजिटल सर्विस एक्ट के तहत मस्क की सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच शुरू की है।

हाई ब्लड शुगर होने पर शरीर के इन अंगों पर पड़ सकता है बुरा असर

डायबिटीज के मामलों में तेजी देखी जा रही है। भारत में डायबिटीज के आंकड़े चिंताजनक है। जी हां, करीब 77 करोड़ लोग इस बीमारी की चपेट में है। वहीं अनुमान जताया जा रहा है कि साल 2045 तक यह संख्या बढ़कर 134करोड़ तक पहुंच जाएगी। अचानक से शरीर में ब्लड के रक्तस्त्राव के बढ़ जाने को हाइपरग्लेसेमिया कहा जाता है। इससे शरीर के कई अंगों को क्षति पहुंचती है।

आंखों की समस्या

डायबिटीज होने के बाद एक अच्छी लाइफस्टाइल से ही अच्छे से लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं। ब्लड शुगर असामान्य रूप से बढ़ने से आंखों पर प्रभाव पड़ता है। इससे धुंधलापन होना, मोतियाबिंद होना, ग्लूकोमा जैसी समस्या घेरने लगती है। इसके लिए पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है।

घाव के ठीक होने में वक्त लगना

दरअसल, हाइपरग्लेसेमिया की वजह से घाव ठीक होने में वक्त लगता है। कई बार महीने भी लग जाते हैं। इतना ही नहीं घाव अगर ठीक नहीं होता है तो कई बार इंफेक्शन नहीं फैले इसलिए अंग को ही निकालना पड़ता है। जिसका कारण होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना।

संक्रमण का खतरा

रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण संक्रमण का खतरा अधिक होता है। डायबिटीज मरीज को यूरिन के संक्रमण का खतरा बहुत अधिक होता है। इसका प्रभाव किडनी पर भी पड़ता है।

पैरों की समस्या

मधुमेह होने के कारण पैर अधिक दर्द करते हैं। कई बार असहनीय दर्द रहता है। पैरों में घाव हो जाना, उंगलियों का कालापन होना।
शुगर कंट्रोल नहीं होने पर पूरे पैर में भी समस्या हो सकती है। इसलिए बेहतर है मीठा जरा भी नहीं खाएं और शुगर फ्री चीजों का ही सेवन करें।

आहार में शामिल करें ये नॉन डेयरी कैल्शियम रिच फूड नहीं होगी कैल्शियम की कमी

शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए दूध और दूध से बने उत्पादों का सेवन बहुत जरूरी होता है। लेकिन यदि आपको दूध पीना पसंद नहीं है या आपको दूध से एलर्जी है तब आप क्या करेंगी? नहीं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रकृति ने हमें ऐसे बहुत से खाद्य पदार्थ दिए हैं, जिनमें उच्च मात्रा में कैल्शियम होता है। इसलिए आज बात करते हैं उन फूड्स की जो दूध के बिना भी आपके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होने देंगे।

क्यों जरूरी है कैल्शियम

हमारे शरीर में हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम बेहद आवश्यक है। यह हड्डियों के साथ ही मांसपेशियों, कोशिकाओं और हृदय व नसों के सुचारू रूप से काम करने के लिए भी बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक पायी जाती है। इनमें से लगभग 98% हिस्सा हमारे दांतो और हमारे शरीर की हड्डियों में प्रयोग होता है। जबकि इसका 1% रक्त और मांसपेशियों में प्रयोग होता है। इसलिए कैल्शियम सभी के लिए आवश्यक है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक कैल्शियम की जरूरत होती है। इसी वजह से कैल्शियम की आपूर्ति के लिए दूध और दूध से बने पदार्थों का सेवन किया जाता है। मगर यदि आपको दूध से एलर्जी है या आपको दूध पीना पसंद नहीं है, तो आपको नॉन डेयरी प्रोडक्ट से यह जरूरत पूरी करनी होगी।

हरी सब्जियां

गहरे रंग वाली सब्जियां जैसे बथुआ, पालक, चौलाई, मेथी आदि में आयरन और फोलेट के साथ-साथ कैल्शियम की भी अच्छी मात्रा होती है। आप इन्हें अपनी डाइट में शामिल कर कैल्शियम की प्राप्ति कर सकती हैं।

बादाम और अंजीर

बादाम को पावर बैंक कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी आवश्यक आयरन और विटामिन होते हैं। यह कैल्शियम में भी काफी समृद्ध होता है। इसी के साथ-साथ अंजीर में भी आयरन और कैल्शियम की समृद्ध मात्रा होती है। नाश्ते, लंच या हल्की स्नैकिंग के रूप में आप बादाम और अंजीर का एक साथ सेवन कर सकती हैं।

डाइट में शामिल करें सोया

यदि आप अपनी डाइट में सोया या उससे बने फूड्स जैसे टोफू का प्रयोग करती हैं तो आपको लगभग 220 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम कैल्शियम की आपूर्ति होती है। जो आपकी दैनिक जरूरत के बराबर है।

भुने हुए तिल

यदि आप कैल्शियम रिच नॉन डेरी प्रोडक्ट की तलाश में हैं, तो भुने हुए तिल आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। एक्सपर्ट के मुताबिक लगभग 25 ग्राम तिल आपको 270 मिलीग्राम कैल्शियम, दैनिक जरूरत के बराबर आपूर्ति करता है।

मछली भी है कैल्शियम रिच

सार्डिन या साल्मन यह दो बेहतरीन मछलियां हैं। जिनसे दैनिक जरूरत की कैल्शियम की आपूर्ति होती है। यह दोनों ही कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड और प्रोटीन के बेहतरीन स्रोत हैं। आपको इनको बस जरूरत के मुताबिक ही खाना है। यानी कि हफ्ते में लगभग दो टुकड़े।

साबुत अनाज एवं दालें

आप अपनी डाइट में ऐसे कुछ अनाज या दालों का प्रयोग कर सकती हैं, जो कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत हैं। जैसे कि मोठ, राजमा, कुलथी, बाजरा, चना, सोयाबीन, रागी आदि।

आयुर्वेद ने भी माना खाली पेट इन चीजों का सेवन करने से घटता है मोटापा

वजन घटाने के लिए लोग न जानें कितनी प्रकार की डायट फॉलो करते हैं। लेकिन अपने आपको भूखा रखकर लंबे समय तक बिना सोचे-समझे किसी भी प्रकार की डायट का पालन करना मुश्किल हो जाता है। वजन घटाना कोई आसान काम नहीं है। शरीर की एक्सट्रा चर्बी को निकालने के लिए नियमित व्यायाम के साथ कैलोरीज भी बर्न करनी पड़ती हैं। इसके लिए आयुर्वेद के पास ऐसे कई तरीके हैं, जिससे शरीर की गंदगी बाहर निकलेगी और आपको वजन कम करने में आसानी होगी। ये तरीके बेहद आसान हैं, लेकिन आपको इन्हें अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना होगा। आइए जानते हैं क्या हैं वो तरीके जिसे मोटापा घटाने के लिए आयुर्वेद में अहम माना गया है.

गर्म पानी के साथ घी और नींबू

200 मिलीलीटर पानी के साथ थोड़ा सा नींबू या घी का सेवन करने से पेरिस्टलसिस में सुधार होता है, जो कि वेस्ट और खाने की गति को नीचे की ओर ढकेलता है। यदि आपका शरीर वात या पित्त प्रकार का है, तो आप इससे आपका पाचन तंत्र चिकना होगा जिससे कब्ज की समस्या दूर होगी।

डायजेस्टिव चाय

आजकल, बाजार में आयुर्वेदिक चाय की ढेर सारी वैराइटीज उपलब्ध हैं। लेकिन अच्छा होगा कि आप घर पर अपनी चाय खुद ही बना लें। इसके लिए 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया के बीज, 1 इलायची और थोड़ी सी अजवाइन को लेकर 500 मिलीलीटर पानी में तब तक उबालें, जब तक पानी की मात्रा आधी न हो जाए। इस चाय को खाली पेट पीने से अपच, ब्लोटिंग और वजन कम करने में मदद मिलेगी।
अपने मेटाबोलिज्म को तेज बनाने के लिए आप दालचीनी, इलायची, लौंग, कद्दूकस की हुई अदरक, काली मिर्च, हल्दी और स्टार ऐनीज को 500 मिली पानी में उबालें। यह पानी आधा हो जाए तब इसमें आधा नींबू और कोकोनट शुगर मिलाएं। चाय शरीर की गर्मी बढ़ाकर चयापचय में सुधार कर के वजन कम करने में मदद करेगी।

कच्चे फल

सुबह खाली पेट हर्बल चाय पीने के बाद, कच्चे फलों का सेवन करें जो प्रकृति में थोड़े से कसैले हो सकते हैं। ग्रीन और रेड एपल, क्रैनबेरी, ब्लूबेरी, चेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, अनानास, आंवला और अनार जैसे फलों को ही चुनें। यह फल शरीर में वॉटर रिटेंशन को कम करते हैं और आपकी त्वचा में कोलेजन को बढ़ाते हैं, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है।

सिलेरी जूस

तनाव से बचने के लिए आयुर्वेद कच्चे फल और पकी या उबली हुई सब्जियां खाने की सलाह देता है। ऐसी स्मूदी लेने से बचें जिसमें फल, सब्जियां, दूध और दही का मिश्रण शामिल हो। यह शरीर में विषाक्त पदार्थों के संचय का कारण बन सकता है। बल्कि पेट की ब्लोटिंग और अतिरिक्त चर्बी को कम करने के लिए एक चुटकी सेंधा नमक और नारियल तेल के साथ सिलेरी का जूस लें।

वजन घटाने के बुनियादी नियम

- जब आपको भूख लगे तब ही खाएं।
- सूर्यास्त के बाद न खाएं।
- इंटरमिटेंट फास्टिंग करें जिसमें 16 घंटे के तक कुछ भी न खाएं। इससे आपकी ऊर्जा तो बढ़ती है साथ में दिमाग पर कंट्रोल रहता है।
- कच्चे फल खाने के बाद पका हुआ भोजन करें।
- आपका पेट केवल आपकी मुट्ठी के आकार का है। अपनी भूख से 80 प्रतिशत भोजन कम खाएं, ताकि खाना पचाने वाले रस अपना काम आसानी से कर सकें।

डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए डाइट में शामिल करें अनार के फूल

खून बढ़ाने से लेकर ग्लोइंग स्किन पाने के लिए अनार खाने के फायदों के बारे में आपने सुना ही होगा। लेकिन क्या आपने अनार के फूल के फायदों के बारे में सुना है। प्राकृति ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया है, जो स्वस्थ रहने और किसी बीमारी से लड़ने के लिए काफी है। ऐसा ही एक प्राकृति का तोहफा है अनार का फूल। आइए जानते हैं अनार के फूल के फायदों के बारे में।

- शुगर की परेशानी इन दिनों आम हो गई है। दुनियाभर में कई लोग इस जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं। हालांकि इसे कंट्रोल करने के कई तरीके हैं, लेकिन बावजूद इसके इसे ठीक नहीं किया जा सकता। ऐसे में एक स्वस्थ जीवन शैली पर स्विच करना महत्तवपूर्ण है। शुगर के मरीजों को कम चीनी और फाईड चीजों को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे में डाइट में अनार के फूल शामिल करना अच्छा हो सकता है। हेल्थ रिपोर्ट्स के मुताबिक अनार के फूल में फोटोकेमिकल होता है, जो शुगर के मरीजों के लिए अच्छा होता है।
- बेदाग स्किन और स्वस्थ चमक इन दिनों खो सी गई है। पर्यावरण प्रदूषण और गलती जीवनशैली के चलते ऐसी त्वचा पाना बेहद ही मुश्किल हो गया है। वहीं बीजी रूटीन में नियमित त्वचा की देखभाल करना भी मुश्किल होता है। ऐसे में आप अनार के फूल पर विश्वास कर सकते हैं, इसकी मदद से झुर्रियों और समय से पहले बूढ़ा होने से बचा जा सकता है।
- कोरोना काल में हर किसी ने एक चीज अच्छे से सिखी है और वो है स्वस्थ्य रहना। लोग इन दिनों स्वस्थ और इम्यूनिटी को बढ़ावा देने वाली हर एक चीज का पूर्ण रूप से ख्याल रख रहे हैं। ऐसे में अनार के फूल भी स्वस्थ रहने में आपकी मदद कर सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जो बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मदद करते हैं।
- अनार के फूल को डाइट में शामिल करने से अपने कार्डियोवस्कुलर हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। शरीर में सबसे महत्तवपूर्ण अंगों में से एक होता है हृदय, जो पूरे शरीर में ब्लड पंप करता है। इससे न केवल ऑक्सीजन बल्कि शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए पोष्क तत्व भी पहुंचाता है। अगर दिल की सेहत का ध्यान न रखा जाए तो आप आलसी, सुस्त और लो एनर्जी महसूस करेंगे।
- अनार का फूल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के साथ शरीर में जमा फैट को खत्म कर आपको हेल्दी रखता है। हालांकि अच्छे परिणाम के लिए आपको कसरत करनी होगी।

कैसे करें अनार के फूल का इस्तेमाल

आप अनार के फूलों के सपलीमेंट ले सकते हैं, या फिर अगर आपको अनार के फूल मिल जाते हैं तो आप इसकी चाय बनाकर पी सकते हैं। हालांकि किसी भी तरह की जलन महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

दूध, दही, पनीर के सेवन से कम होता है डायबिटीज और हाई बीपी का खतरा

वैज्ञानिकों के अनुसार दही, दूध या पनीर का रोजाना सेवन डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा कम करता है। हाल ही में एक शोध ने डेयरी रिच डाइट (यानी दही, दूध या पनीर युक्त खाद्य पदार्थ) को रक्त शर्करा के स्तर, ब्लड प्रेशर में सुधार और हृदय रोग संबंधी जोखिमों को कम करने से जोड़ा गया। शोध के मुताबिक, रोजाना इन डेयरी उत्पादों का दो बार सेवन इन बीमारियों से राहत दिलाने में फायदा करता है।

इस अध्ययन को डायबिटीज रिसर्च जर्नल में प्रकाशित किया गया। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य पर डेयरी उत्पादों के प्रभाव का विश्लेषण करना था। उन्होंने भारत सहित दुनियाभर के 21 देशों के 35 से 70 वर्ष के लोगों में डेयरी रिच डाइट के प्रभाव का गहराई से अध्ययन किया। इस शो में डेयरी उत्पादों जैसे दूध, दही, दही से बने पेय, पनीर से बनी डिशेज शामिल थीं। इन्हें फुल या लो फैट के रूप में बांटा गया था। बटर और क्रीम का अलग से मूल्यांकन किया गया था, क्योंकि वे आमतौर पर उन देशों में नहीं खाए जाते थे जो अध्ययन का हिस्सा थे।
मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पांच घटकों पर डेयरी उत्पादों के प्रभाव का अध्ययन किया गया था। यह अध्ययन लगभग 1,13,000 लोगों में किया गया। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक तरह से समस्याओं का झुंड होता है। मुख्य रूप से इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ना, ब्लड शुगर बढ़ जाना, कमर के आसपास चर्बी बढ़ जाना और कोलेस्ट्रॉल व ट्राइग्लिसराइड का स्तर असामान्य हो जाना जैसी समस्याएं शामिल होती हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ये समस्याएं एक साथ होती हैं जिससे स्ट्रोक, डायबिटीज व हृदय संबंधी बीमारियां होने का जोखिम बढ़ जाता है।
शोधकर्ताओं ने हाई ब्लड प्रेशर, बढ़ी हुई कमर, गुड कोलेस्ट्रॉल का निम्न स्तर, हाई ब्लड फैट्स और बढ़े हुए फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज की 12 महीनों की स्थिति को ट्रैक किया। अध्ययन से पहले लगभग 46,667 लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम था, यानी उनमें पांच में से कम से कम तीन स्थितियां थीं। शोधकर्ताओं ने पाया कि फुल फैट वाले डेयरी का सेवन करने से मेटाबॉलिक सिंड्रोम का जोखिम कम था। इससे पता चलता है कि डेयरी प्रोडक्ट शरीर की कार्यप्रणाली में कैसे सुधार करते हैं। शोध में कहा गया है कि यदि इन निष्कर्षों के आधार पर बड़े और दीर्घकालिक परीक्षणों में पुष्टि की जाती है, तो बढ़ती डेयरी खपत मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज और हृदय रोग के मामलों को कम करने के लिए बड़े काम की हो सकती है।
डेयरी उत्पादों में स्वास्थ्य लाभ में हड्डियों, दांतों और मांसपेशियों की मजबूती, पाचन में सुधार, वजन घटाना आदि शामिल हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक डेयरी उत्पाद प्रोटीन और कैल्शियम के बड़े स्रोत हैं। इसके अलावा यह उत्पाद विटामिन और मिनरल्स के भी बड़े संयोजक होते हैं। डेयरी उत्पाद मुख्य रूप से पशुओं के दूध से निर्मित खाद्य या पेय पदार्थ होते हैं। मुख्य रूप से जिन पशुओं के दूध का प्रयोग इन उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है उनमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़, याक और ऊंट शामिल हैं।

हेल्दी डाइट के लिए खाइए ब्राउन राइस

जो लोग हेल्दी डाइट और व वजन कम करने में दिलचस्पी रखते हैं और चावल से परहेज करते हैं, उनके लिए ब्राउन राइस एक बेहतरीन विकल्प है। कैलोरी कम होने के साथ-साथ इसके और भी कुछ फायदे हैं। जानिए इसके 5 फायदे.

कोलेस्ट्रॉल

ब्राउन राइस खाने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अनचाहे फैट को शरीर के आंतरिक भागों में जमने से रोकता है।

डाइबिटीज

सामान्यत: चावल में शर्करा की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण डाइबिटीज के रोगी इससे दूरी बनाए रखते हैं। लेकिन ब्राउन राइस के सेवन से रक्त में शर्करा का स्तर नहीं बढ़ता। इसलिए यह आपके लिए बेहतर विकल्प है।

हृदय रोग

हार्टअटैक या हृदय के अन्य रोग, ज्यादातर हृदय की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल के जमाव के कारण होते हैं। ऐसे में ब्राउन राइस का सेवन इससे बचाकर आपके हृदय की भी रक्षा करता है।

हड्डियां

मैग्नीशियम व कैल्शियम से भरपूर होने के कारण ब्राउन राइस, हड्डियों को मजबूत करने के लिए बेहद फायदेमंद है। सफेछ चावल की अपेक्षा यह सेहत के कई फायदे देता है।

वजन कम

वजन कम करना चाहते हैं, और चावल से दूर नहीं रह सकते, तो सफेद चावल की जगह ब्राउन राइस को भोजन में शामिल करें। कुछ ही समय में आप वजन में कमी महसूस करेंगे।

जरूरी नहीं महंगी बादाम खाना, सस्ती मूंगफली भी है प्रोटीन का खजाना

मूंगफली का सेवन सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। बल्कि इसे बादाम का पर्याय माना जाता है। जितने पोषक तत्व बादाम में मौजूद होते हैं वह सभी मूंगफली में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन बादाम महंगा होता है और मूंगफली सस्ती होती है लेकिन आप बादाम की जगह मूंगफली भी खा सकते हैं। एक लीटर दूध के बजाए 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में अधिक प्रोटीन होता है। मूंगफली के साथ ही मूंगफली के तेल के कई फायदे होते हैं। यह कीटाणुओं को खत्म करने में मददगार होता है। जानते हैं मूंगफली खाने के अचूक फायदों के बारे में -

हड्डियों को करें मजबूत

मूंगफली के सेवन से हड्डियां मजबूत होती है। मूंगफली में मौजूद पोषक तत्वों से शरीर को विटामिन डी और कैल्शियम मिलता है। बादाम के बदले इसका आसानी से सेवन कर सकते हैं।

हार्मोन को करें बैलेंस

जब महिला और पुरुषों में हार्मोंस अनबैलेंस्ड हो जाते हैं तब कई प्रकार की शारीरिक समस्या होती है। इसलिए महिला और पुरुष को रोज एक मुट्ठी मूंगफली का सेवन करना चाहिए।

कैंसर से बचाएं

मूंगफली में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसका नाम है पॉलीफिनॉलिक। इसके सेवन से पेट के कैंसर का खतरा कम हो जाता है। सप्ताह में 1 बार मूंगफली के साथ मक्खन का सेवन करना चाहिए।

झुर्रियों को हटाए

मूंगफली खाने से झुर्रियां कम होती है। इसमें मौजूद तत्व चेहरे पर बारीक रेखा और झुर्रियों को बनने से रोकती है।

ड्रायबिटीज को करें नियंत्रित

मूंगफली का सेवन करने से डायबिटीज की आशंका कम होती है। रोज अपनी डाइट में इसे जरूर शामिल करना चाहिए। ताकि घातक बीमारियों से बचा जा सकें।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए आरडब्ल्यूए को पैसे देगी आप

नईदिल्ली। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एक चुनावी वादे में कहा कि दिल्ली में उनकी पार्टी के सत्ता में लौटने के बाद आरडब्ल्यूए को निजी सुरक्षा गार्ड नियुक्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने दिल्ली को भारत की अपराध राजधानी बना दिया है। दिल्ली में डकैती, चेन स्नैचिंग, गैंगवार हो रहे हैं; महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बीजेपी को दिल्ली के लोगों से नफरत है। उनकी नफरत के कारण ही वे पिछले 25 वर्षों में दिल्ली की सत्ता में वापस नहीं लौटे हैं। केजरीवाल ने ऐलान करते हुए कहा कि मैंने दिल्ली के लोगों को आश्वासन दिया है कि आप सरकार बनने पर आरडब्ल्यूए को अपने-अपने क्षेत्रों में निजी सुरक्षा गार्ड नियुक्त करने के लिए दिल्ली सरकार से धन मिलेगा। पुलिस को बदलना हमारा उद्देश्य नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा अब धरना पार्टी बन गयी है।

केजरीवाल के खिलाफ भाजपा का हल्ला बोल

नईदिल्ली। दिल्ली में पूर्वांचलियों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही है। भाजपा की ओर से पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाला गया है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाल रहे और केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को हिरासत में ले लिया। पूर्वांचल के मतदाताओं पर दिए गए बयान को लेकर केजरीवाल के फिरोजशाह रोड स्थित आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। इससे पहले केजरीवाल के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। वहीं, पूर्वांचली मुद्दे पर बोले आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मैं दिल्ली के पूर्वांचली नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जब जेपी नड्डा ने पूर्वांचलियों को घुसपैठिया कहा था तब मनोज तिवारी कहां थे।

वोट खरीदने के लिए भाजपा ने खुलेआम बांटे रुपये : संजय

नईदिल्ली। आप सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर तीखा हमला बोला। आप सांसद ने एक राजनीतिक दल पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और इसे गाली गलौज पार्टी कहा। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी पार्टी के नेताओं ने वोट खरीदने के लिए खुलेआम 1100 रुपये बांटे। सिंह ने आगे कहा कि हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि गाली-गैलोच पार्टी के नेताओं को उनकी पार्टी की ओर से 10-10 हजार रुपये बांटने के लिए दिए गए थे। उनके नेताओं ने सोचा कि जब चुनाव जीतने की कोई संभावना नहीं है, तो उन्हें 9000 रुपये बचाना चाहिए और केवल 1100 रुपये बांटना चाहिए। संजय सिंह ने पार्टी को सच्चाई उजागर करने की चुनौती देते हुए पूछा कि क्या आपने अपने नेताओं को मतदाताओं के बीच बांटने के लिए 1,100 रुपये दिए थे या नहीं? जनता को हकीकत बताएं...मैं गाली-गलौज पार्टी से लोगों के सामने सच्चाई बताने को कहता हूं।

लालू यादव के करीबी विधायक के घर ईडी का छापा

पटना। ईडी ने एक निजी सहकारी बैंक से ऋण वितरण में कथित घोर अनियमितताओं के संबंध में बिहार के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ राजद नेता आलोक कुमार मेहता से जुड़े 19 स्थानों पर तलाशी की है। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद विधायक मेहता को लालू प्रसाद का करीबी माना जाता है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम की अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि निवर्तमान जगदानंद सिंह के 18 जनवरी को कार्यकारी समिति की बैठक में पद छोड़ने की उम्मीद है। पटना और हाजीपुर में नौ स्थानों, दिल्ली में एक स्थान, कोलकाता में पांच और उत्तर प्रदेश में चार स्थानों पर एक साथ तलाशी ली जा रही है। ईडी के अधिकारियों ने शुक्रवार सुबह राज्य की राजधानी में मेहता के विधायक फ्लैट को घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू किया। जब ईडी अधिकारी अदालत का आदेश लेकर पहुंचे तो मेहता अपने आवास पर मौजूद थे। यह जांच वैशाली शहरी विकास सहकारी बैंक से 60 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण वितरण से संबंधित है।

कुंभ से बड़ा है गंगासागर मेलाः ममता बनर्जी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को दावा किया कि गंगासागर मेला कुंभ मेले से भी बड़ा है और इसलिए केंद्र को इसे राष्ट्रीय मेले का दर्जा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र कुंभ मेले के आयोजन के लिए हजारों करोड़ रुपये मुहैया कराता है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार को सभी प्रावधान करने होते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर कपिल मुनि मंदिर में आयोजित किया जाता है। बनर्जी ने यहां गंगा (हुगली) नदी के तट पर आउट्राम घाट पारगमन बिंदु से मेले का उद्घाटन करने के बाद कहा कि हम पिछले 10 वर्षों से गंगासागर मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिलाने की व्यर्थ कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यह कुंभ मेले से कम नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ा है। उन्होंने कहा कि देश के कोने-कोने से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए, मेला स्थल पर विभिन्न भाषाओं में घोषणाएं की जाएंगी।

कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में और बढ़ी तकरार!

विपक्षी गठबंधन के अस्तित्व पर उठ रहे सवालों के लिए कांग्रेस जिम्मेदार: राउत

मुंबई। इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा कि लोकसभा चुनाव के अच्छे नतीजों के बाद कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि वह गठबंधन को जिंदा रखें और सभी दलों को एकजुट करके आगे का रास्ता दिखाएं। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक गठबंधन की कोई बैठक नहीं हुई है, जिससे लोगों में संदेह उत्पन्न हो रहा है।

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा, हमने लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ा था और नतीजे भी अच्छे आए थे। उसके बाद हम सभी की, खासकर कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि हम इंडिया गठबंधन को जिंदा रखें, साथ बैठें और आगे का रास्ता दिखाएं। लेकिन अब तक लोकसभा चुनाव के बाद ऐसी एक भी बैठक नहीं हुई है। यह इंडिया गठबंधन के लिए सही नहीं है।

उन्होंने आगे कहा, उमर अब्दुल्ला, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं का कहना है कि गठबंधन का अब कोई अस्तित्व नहीं है। अगर लोगों के मन में ऐसी भावना आती है तो इसके लिए विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस जिम्मेदार है। कोई समन्वय नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कोई संवाद नहीं है। इसका मतलब है कि लोगों को संदेह है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है या नहीं। अगर यह एक बार टूट गया तो इंडिया गठबंधन फिर कभी नहीं बनेगा।

विपक्षी गठबंधन पर राजद सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर एक विकल्प प्रदान करने के लिए था। राज्यों में स्थितियां पूरी तरह से अलग हैं। तेजस्वी यादव ने भी यही बात कही थी। यही विपक्षी गठबंधन का मूल मंत्र है। इंडिया गठबंधन एक विचार था और यह विचार कभी खत्म नहीं होगा।

डी राजा ने भी माना, बंटा हुआ है विपक्ष

2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्षितिज पर उभरा इंद्रधनुषी विपक्षी इंडिया गठबंधन अब तूफान की राह पर है। इसमें दिल्ली चुनाव के बीच जबरदस्त बिखराव देखने को मिल रहा है। आप और कांग्रेस आमने-सामने हैं। वहीं, गठबंधन में शामिल दलों की ओर से कुछ ऐसे बयान सामने आए हैं जिसके बाद गठबंधन को लेकर संशय बढ़ गया है। सीपीआई महासचिव डी राजा ने भी स्वीकार किया है कि विपक्ष बंटा हुआ है। एक बयान में उन्होंने कहा कि लोगों को पता है कि दिल्ली चुनाव में आप अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। राजा ने कहा कि वामपंथी दल जहां भी लड़ने में सक्षम हैं वहां चुनाव लड़ रहे हैं और अन्य पार्टियों ने से कुछ पार्टियों ने आप को समर्थन देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ऐसे में तो, यह एक सच्चाई है कि इंडिया गुट विभाजित है। जहां तक वाम दलों का सवाल है, पटना में हुई पहली बैठक के बाद से हम इस राजनीतिक विचारधारा पर चल रहे हैं कि हमारा प्राथमिक उद्देश्य भाजपा को हराना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा प्रयास सभी स्तरों पर धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक दलों को एकजुट करना होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन वामपंथी इस बात का प्रयास करेंगे कि धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक दलों को कैसे एकजुट किया जाए, जहां भी आवश्यक हो, भाजपा की हार सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत, सामूहिक लड़ाई लड़ी जाए।

ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी मामले में स्ट ने कंपनियों को दी राहत

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जारी किए गए 1.12 लाख करोड़ रुपये के वस्तु एवं सेवा कर (जस्ट) %कारण बताओ नोटिस% पर रोक लगा दी, जिससे इस सेक्टर को अस्थायी राहत मिली है।शीर्ष अदालत ने मामले के अंतिम निपटारे तक डीजीजीआई द्वारा जारी सभी %कारण बताओ नोटिस% के संबंध में आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी।मामले की अंतिम सुनवाई 18 मार्च को तय की गई है। फैसले के बाद, स्टॉक एक्सचेंजों पर इंट्रा-डे ट्रेड के दौरान डेल्टा कॉर्प और नाजारा टेक जैसी गेमिंग कंपनियों के शेयरों में 7 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई।

ई-गेमिंग फेडरेशन (ईजीएफ) के सीईओ अनुराग सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई राहत का स्वागत किया।सक्सेना ने कहा, यह सरकार और गेमिंग ऑपरेटर्स दोनों के लिए फायदेमंद है। गेमिंग ऑपरेटर्स के लिए जो जबरदस्ती की कार्रवाई का सामना कर रहे थे और सरकार के लिए जिसकी समयसीमा अब बढ़ाई जा सकती है। हम इस मुद्दे के निष्पक्ष और प्रगतिशील समाधान को लेकर आश्वस्त हैं, जिसके बाद हम गेमिंग सेक्टर में निवेश, रोजगार और वैल्यूएशन को अपनी पूरी क्षमता तक बढ़ते देखेंगे।डीजीजीआई ने 2023 में गेमिंग कंपनियों को 71 नोटिस भेजे, जिसमें उन पर 2022-23 और 2023-24 के पहले सात महीनों के दौरान 1.12 लाख करोड़ रुपये के जीएसटी की चोरी करने का आरोप लगाया गया, जिसमें ब्याज और जुर्माना शामिल नहीं है।

जीएसटी अधिनियम की धारा 74 के तहत नोटिस जारी किए गए थे, जो विभाग को कर मांग के 100 प्रतिशत तक का जुर्माना लगाने की अनुमति देता है और कुल देयता ब्याज सहित 2.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है।अगस्त 2023 में, जीएसटी परिषद ने कानून में संशोधन किया, जिसमें कहा गया कि दांव लगाने वाले सभी ऑनलाइन गेम, स्किल या चांस की परवाह किए बिना, उसी वर्ष 1 अक्टूबर से लगाए गए दांव के पूरे मूल्य पर 28 प्रतिशत की जीएसटी दर लगेगी, न कि सकल गेमिंग राजस्व पर।

शरद पवार ने आरएसएस की जमकर की तारीफ

संघ की मेहनत के कारण महाराष्ट्र में जीती भाजपा : पवार

मुंबई। राकांपा (सपा) प्रमुख शरद पवार ने अपनी विचारधारा के प्रति समर्पण के लिए आरएसएस की प्रशंसा की है और अपनी पार्टी से शाहू महाराज, महात्मा फुले, बीआर अंबेडकर और राजनीतिक दिग्गज यशवंतराव चव्हाण के प्रगतिशील विचारों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ एक कार्यकर्ता आधार बनाने का आग्रह किया है। दक्षिण मुंबई में एक बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पास समर्पित कैडर हैं जो हिंदुत्व संगठन की विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा दिखाते हैं और किसी भी कीमत पर अपने रास्ते से नहीं हटते हैं।

सूत्रों के अनुसार, मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, अनुभवी राजनेता ने कहा कि पिछले साल नवंबर के चुनावों में भाजपा की सफलता के पीछे आरएसएस की कार्य पद्धति और उसका आक्रामक हिंदुत्व अभियान प्रमुख स्तंभ थे, जहां पार्टी ने 149 सीटों पर चुनाव लड़कर 132 सीटें जीतीं। पवार, जिनकी पार्टी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, ने 1957 में सफाए के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस के पुनरुद्धार को याद किया। उन्होंने असफलताओं का सामना करने के बावजूद 1962 और 1977 में पार्टी की जीत पर प्रकाश डाला।

पवार ने कहा कि हमारे पास भी ऐसा कैडर बेस होना चाहिए जो छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा फुले, बीआर अंबेडकर और यशवंतराव चव्हाण की विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध हो। महाराष्ट्र में नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (सपा) की बुरी हार पर विचार करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में सफलता के बाद हम आत्मसंतुष्ट हो गए, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन (भाजपा नीत महायुति) ने संसदीय चुनावों में अपनी हार को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए। समर्पित आरएसएस कार्यकर्ताओं का उदाहरण देते हुए, पवार ने जमीनी स्तर तक संगठन के सावधानीपूर्वक काम को भी स्वीकार किया। 17 नए राज्य-संचालित निगमों की स्थापना करके भाजपा के मूल अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) वोट बैंक का विश्वास वापस जीतना भी पवार द्वारा एनडीए की जीत के प्रमुख कारणों में से एक के रूप में देखा गया था।

कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम पर सीबीआई ने दर्ज किया नया केस

नईदिल्ली। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के सांसद बेटे कार्ति चिदंबरम की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम पर संदिग्ध वित्तीय लेनदेन और भ्रष्टाचार से जुड़ा नया मामला दर्ज किया है। कार्ति चिदंबरम को सीबीआई ने सिकोइया कैपिटल मॉरीशस, एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (एएससीपीएल) और बसंत हेल्थ केयर के साथ सह आरोपी बनाया है। सीबीआई ने ये नया मामला 2008 में भारत में टैक्स फ्री शराब की बिक्री के लिए डियाजियो स्कॉटलैंड पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने में की गई कथित अनियमितताओं को लेकर दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की शुरुआती जांच में पता चला है कि सिकोइया कैपिटल मॉरीशस और एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ बसंत हेल्थ केयर के जरिए संदिग्ध लेन-देन हुई थी। जांच में खुलासा हुआ है कि बसंत समूह से सीधे शेयर खरीदने के बजाय एएससीपीएल के माध्यम से इसे खरीदा गया। ऐसा कार्ति चिदंबरम को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था।

खेल
प्रमुख समाचार

इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में नहीं खेलेंगे केएल राहुल?

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद भारतीय टीम अब सीमित ओवरों के प्रारूप की तैयारियों में जुट गई है। भारत को इस महीने के अंत में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज खेलनी है जिसके लिए अगले कुछ दिनों में भारतीय टीम घोषित हो सकती है। भारत को अगले महीने चैंपियंस ट्रॉफी में भी हिस्सा लेना है और माना जा रहा है कि इसे देखते हुए केएल राहुल को इंग्लैंड के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज से आराम दिया जा सकता है।

भारत और इंग्लैंड के बीच 22 जनवरी से पांच मैचों की टी20 सीरीज होनी है। इसके बाद दोनों टीमें तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेंगी। फिर टीम 19 फरवरी से हाइब्रिड मॉडल के तर्ज पर होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेगी। केएल राहुल भले ही इंग्लैंड के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज का हिस्सा ना रहें, लेकिन वह 50 ओवर के प्रारूप में आठ टीमों के बीच होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध होंगे।

भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इन्कार कर दिया था और भारत अपने सभी मैच दुबई में खेलेगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के एक सूत्र ने न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से कहा, केएल राहुल ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से ब्रेक मांगा है, लेकिन वह चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया था, लेकिन राहुल उन कुछ बल्लेबाजों में से थे जिन्होंने रन बनाए। वह 10 पारियों में 30.66 की औसत से 276 रन बनाकर भारत के लिए तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। सीमित ओवरों की टीम में राहुल को जगह बनाने के लिए ऋषभ पंत और संजू सैमसन जैसे विकेटकीपर बल्लेबाज की चुनौती का सामना करना होगा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 241 अंक टूटा, निफ्टी 23,500 के नीचे फिसला

नईदिल्ली। वैश्विक बाजारों में मिलेजुले रुख के बीच आईटी स्टॉक्स में तेजी के बावजूद घरेलू शेयर बाजार लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन में गिरकर बंद हुए। कंपनियों के तीसरी तिमाही के नतीजे सुस्त रहने की आशंका और अमेरिकी ब्याज दरों में कम बार कटौती की बढ़ती संभावनाओं ने मार्केट के सेंटीमेंट को प्रभावित किया है। इसके अलावा विदेशी निवेशकों की बिकवाली के कारण इस सप्ताह बाजार दबाव में दिखे हैं। बीएसई सेंसेक्स शुक्रवार (10 जनवरी) को बढ़त के साथ 77,682 अंक पर खुला। कारोबार के दौरान यह 600 से ज्यादा अंक तक लुढ़क गया था। अंत में सेंसेक्स 241.30 अंक या 0.31% की गिरावट लेकर 77,378.91 पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी50 भी बढ़त लेकर खुला। मगर यह भी कुछ ही देर में लाल निशान में चला गया। अंत में निफ्टी 95. अंक या 0.4% गिरकर 23,431 पर क्लोज हुआ।

स्माल कैप फंड में निवेश का मौका

नईदिल्ली। एसेट मैनेजमेंट कंपनी मिराए एसेट म्युचुअल फंड का नया फंड शुक्रवार (10 जनवरी) को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया। म्युचुअल फंड हाउस ने इक्विटी कैटेगरी में नई स्कीम मिराए एसेट स्मालकैप फंड लॉन्च की है। इस ओपन-एंडेड स्कीम में 24 जनवरी 2025 तक आवेदन किया जा सकता है। यह स्कीम मुख्य रूप से स्मॉलकैप शेयरों पर फोकस करेगी। फंड का बेंचमार्क निफ्टी स्मॉलकैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। मिराए एसेट म्युचुअल फंड के मुताबिक, शेयर बाजार में निवेश के जरिए अपनी पूंजी बढ़ाना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए खास हो सकती है। इस निवेश योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे कैप शेयरों में पैसा लगाकर पूंजी में वृद्धि करना है। फंड मैनेजर समय-समय पर अन्य इक्विटी और उससे जुड़ी प्रतिभूतियों में भी निवेश करेंगे, ताकि पोर्टफोलियो को बेहतर तरीके से तैयार किया जा सके।

2025 में 6.6 फीसदी रहेगी भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट

नईदिल्ली। भारतीय अर्थव्यवस्था में 2025 में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, जिसे मुख्य रूप से मजबूत निजी खपत तथा निवेश का समर्थन मिलेगा। साथ ही, दक्षिण एशिया में आर्थिक वृद्धि इस साल मजबूत रहने की उम्मीद है, जो मुख्य रूप से भारत के ''मजबूत प्रदर्शन'' से प्रेरित रहेगी। 'संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति व संभावना 2025' रिपोर्ट में यह बात कही गई जिसे बुधवार को जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि दक्षिण एशिया के लिए निकट अवधि का परिदृश्य मजबूत रहने की उम्मीद है, जिसमें 2025 में 5.7 प्रतिशत और 2026 में 6.0 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। यह भारत में मजबूत प्रदर्शन के साथ-साथ भूटान, नेपाल तथा श्रीलंका सहित कुछ अन्य अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक सुधार से प्रेरित है। भारतीय अर्थव्यवस्था के 2024 में 6.8% की दर से और 2025 में 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था के 2026 में फिर 6.8% की वृद्धि पर लौटने का अनुमान है।

खाद्य कीमतों में नरमी का दिख रहा है असर : सर्वे

नईदिल्ली। भारत में खुदरा मूल्य मुद्रास्फीति दिसंबर में घटकर 5.3 प्रतिशत पर आने की संभावना है। यह कमी मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में गिरावट के कारण हुई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अर्थशास्त्रियों द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार, इससे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अगले महीने ब्याज दर में कटौती की उम्मीदें मजबूत हुई हैं, खासकर जब आर्थिक वृद्धि धीमी हो रही है। खाद्य कीमतें, जो देश के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की टोकरी का लगभग आधा हिस्सा बनाती हैं, हाल के महीनों में महंगाई को ऊंचा रख रहा थीं। खासतौर पर सब्जियों की कीमतों में पिछले एक साल से दो अंकों की बढ़ोतरी हो रही थी। हालांकि, एक अच्छी ग्रीष्मकालीन फसल और अनुकूल मानसून के कारण इन कीमतों में अब कमी देखी जा रही है, जिससे आने वाले महीनों में और गिरावट की उम्मीद है।

घरेलू खपत बढ़ने से अर्थव्यवस्था में बेहतरी की उम्मीद

मधुरेंद्र सिन्हा

बीते वर्ष भारत की जीडीपी की दर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी बनी रही। उसने निराशा के दौर से गुजरती दुनिया को नया रास्ता दिखाया। वर्ष 2024 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका में भी भारत की चर्चा रही। भारतीय मूल के वोटरों को रिझाने के लिए दोनों बड़ी पार्टियों ने ताकत लगायी और उनकी उम्मीदवारी भी की। यह केवल इसलिए नहीं हुआ कि अमेरिका में 26 लाख भारतीय मूल के वोटर थे, बल्कि इसलिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक तारे की तरह चमक रही थी जिससे अमेरिका को आर्थिक तथा राजनीतिक मित्रता की दरकार है।

भारत की अर्थव्यवस्था बीते साल मजबूती से बढ़ती रही। चुनाव में सत्तारूढ़ दल की विजय के बाद राजनीतिक स्थिरता बनी रहने के कारण उसमें तेजी ही आयी। हालांकि विकास दर अप्रैल से जून की अवधि में 6.7 प्रतिशत रही जो पिछली पांच तिमाहियों में सबसे कम थी। इसके बावजूद यह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक रही। इसकी यह गति देखकर अंतरराष्ट्रीय रेटिंग और वित्तीय एजेंसियों ने माना कि आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक शक्ति और बढ़ेगी। यहां विकास की गति बढ़ेगी और उसका आधार घरेलू खपत या उपभोग रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग बढ़ेगा क्योंकि कृषि विकास की गति तेज होगी। संतुलित मानसून के कारण फसलें अधिक होंगी जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और वे खर्च करेंगे।

अंतरराष्ट्रीय एजेंसी डेलॉएट का तो कहना है कि 2024-25 में भारत के जीडीपी विकास की दर सात से 7.2 प्रतिशत रहेगी और उसके बाद के वित्त वर्ष में यह 6.5 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत के बीच रहेगी। यह रफ्तार भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने देने के लिए जरूरी है। भारत में आने वाले वर्षों में विदेशी निवेश और बढ़ेगा। चीन से कई कंपनियां भारत सहित कई अन्य देशों की ओर जायेंगी जिससे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। इस समय देश में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का कुल जीडीपी में योगदान 20 प्रतिशत ही है और इसे बढ़ाने की जरूरत है। विदेशी पूंजी के भारत आने के अपने लाभ होंगे।

भारत ने जितनी तेजी से एक बड़े अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर रेल, वायु और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया तथा उसमें निरंतर विकास जारी है, वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों को पसंद आ रहा है। पर्याप्त इंफ्रा के बिना भारत में बड़े पैमाने पर निवेश नहीं हो पाता, न ही इसकी गुंजाइश होती। इतना ही नहीं, भारत के श्रम बाजार की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है और अब अधिक से अधिक कुशल तथा प्रशिक्षित श्रमिक सामने आ रहे हैं। उनकी उत्पादकता पहले से बेहतर है। हालांकि 2024 के अंत में सितंबर तिमाही जीडीपी के आंकड़ों ने वित्त मंत्रालय को निराश कर दिया।

अर्थव्यवस्था की गति में सुस्ती आ गयी और यह गिरकर 5.4 प्रतिशत पर आ गयी जबकि आकलन था कि यह 6.4 प्रतिशत तक हो सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण था कि लोगों की खपत करने की क्षमता में भारी कमी आयी है, क्योंकि देश में रोजमर्रा की चीजों की महंगाई बढ़ी और खर्च के लिए लोगों के पास अतिरिक्त धन नहीं था। इसके अतिरिक्त, सरकारी खर्च में भी कमी आयी। इसके पहले की अवधि, यानी जुलाई-सितंबर में यह 7.4 प्रतिशत था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बार इस बात पर जोर दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था खपत या उपभोग आधारित है। इसका अर्थ हुआ कि जब खपत बढ़ेगी तो जीडीपी में भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन इस वर्ष इस घरेलू खपत में गिरावट देखी गयी। कई उद्योगों के बिक्री के आंकड़ों ने तो बहुत निराश किया। इसमें ऑटोमोबाइल उद्योग भी था जिसकी बढ़ती ताकत की चर्चा चारों ओर हो रही थी। ऑटोमोबाइल उद्योग मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ की हड्डी बनता जा रहा है। वर्ष 2025 में इसके विकास की दर 11 प्रतिशत से भी अधिक रहने की उम्मीद जतायी जा रही है, जिसका असर विकास दर पर भी पड़ेगा।

इंडिया अलायंस पर संविधान के प्रति दुष्प्रचार के आरोप, बीजेपी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण

संविधान गौरव अभियान आज से आगाज

रायपुर। गणतंत्र दिवस से पहले संविधान के प्रति सम्मान और उसके मूल्य को बढ़ावा देने के लिए एक पखवाड़े तक चलने वाला अभियान 11 जनवरी से शुरू होगा. इस बात की जानकारी शुक्रवार को भाजपा के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने मीडिया कर्मियों को दी.

आज से शुरू होगा अभियान

गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि संविधान गौरव अभियान अखिल भारतीय स्तर पर 11 जनवरी से लेकर पखवाड़े भर तक चलेगा. संविधान के प्रति जैसा दुष्प्रचार कांग्रेस पार्टी और उनके साथियों के द्वारा किया जा रहा है इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि संविधान आस्था और श्रद्धा का विषय है. संविधान सत्ता प्राप्ति का विषय नहीं हो सकता है.

कांग्रेस को बताया अंबेडकर विरोधी

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के युवराज यानी राहुल गांधी, जो कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करते हैं. मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे स्वयं को संविधान के ऊपर मानते हैं. कांग्रेस पार्टी की मानसिकता आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है और सामाजिक न्याय विरोधी है. बाबा साहब अंबेडकर विरोधी है.

कांग्रेस पर संविधान के प्रति दुष्प्रचार के आरोप

गुरु प्रकाश पासवान, राष्ट्रीय प्रवक्ता, बीजेपी ने कहा कि सन 1952 के चुनाव में बाबा साहब अंबेडकर का सदन में प्रवेश रोकने का विषय हो, बाबा साहब अंबेडकर का केंद्रीय कैबिनेट में अपमान का हो, बाबा साहब अंबेडकर ने चिट्ठियों के जरिए अपनी पीड़ा को कई बार व्यक्त किया है. एक तरफ वह लोग हैं, जो बाबा साहब के साहित्य को जलाते हैं और एक तरफ हम लोग हैं, जो साल 2015 में बाबा साहब अंबेडकर से जुड़े सभी साहित्य का डिजिटल वर्जन उपलब्ध कराते हैं।

महाराष्ट्र की जनता ने कांग्रेस को किया पराजित

गुरु प्रकाश पासवान ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी या फिर कोई दूसरी पॉलीटिकल पार्टी हो, किसी के पास सामाजिक न्याय, बाबा साहब अंबेडकर और संविधान की जिम्मेदारी नहीं हो सकती. संविधान अगर किसी का है तो वह देश के 140 करोड़ लोगों का है. महाराष्ट्र फुले, सावरकर और अंबेडकर की भूमि है, जहां की देवतुल्य जनता ने 288 में से 235 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर कांग्रेस को पराजित किया है.

गुरु प्रकाश पासवान, ने कहा कि संविधान के प्रति संवेदनशीलता, संविधान के प्रति सम्मान, संविधान के प्रति, बाबा साहब के आदर्श के प्रति एक मजबूत संकल्प लेकर भाजपा पूरे देश और छत्तीसगढ़ में 11 जनवरी से 26 जनवरी तक बड़े कार्यक्रम, बस्ती स्टार के कार्यक्रम और संपर्क के कार्यक्रम से संविधान के प्रति कांग्रेस के दुष्प्रचार के खिलाफ अभियान चलाएंगे।

कांग्रेस पार्टी को बताया आरक्षण विरोधी

गुरु प्रकाश पासवान का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में, वह चाहे संविधान दिवस हो, चाहे संविधान दिवस की विधिवत घोषणा हो. वह चाहे बाबा साहब अंबेडकर के 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश को गजट में डलवाने की बात हो. चाहे बाबा साहब अंबेडकर को सम्मानित करना हो, चाहे सदन में बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लगाना हो. कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार आरक्षण का विरोध करते आए हैं. आदिवासी की बेटी को संविधान के सर्वोच्च स्तर पर बैठने का मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया है.

पानी प्रकृति का अनमोल उपहार: सीएम साय

रायपुर । पानी प्रकृति का अनमोल उपहार है, जिसे ईश्वर ने हमें बेमोल दिया है, लेकिन हमें इसका मोल समझना होगा। आज पूरा विश्व जल संकट से जूझ रहा है। देश-दुनिया के कई शहरों में भू जल स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है। यदि समय रहते हम सचेत नहीं हुए तो जल संकट विकराल रूप धारण कर सकता है। हम सभी को पानी की एक-एक बूंद को सहेजना होगा। जल संरक्षण की जिम्मेदारी हम सबकी है। जल प्रबंधन आज समय की मांग है। हमें आने वाली पीढ़ियों के बेहतर जीवन के लिए जल के प्रबंधन, संरक्षण के साथ ही जल स्रोतों के संवर्धन पर विशेष ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन के 57वें वार्षिक अधिवेशन को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक जलवायु संकट के परिपेक्ष्य में जल संरक्षण और भी महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जल संरक्षण के लिए जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान, अमृत सरोवर, मिशन अमृत और एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियान शुरू कर जल और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मोदी जी ने प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हर घर नल से जल योजना शुरू की। हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नल कनेक्शन प्रदान किया है।,

बिजली बिल बकाया वसूली के लिए चलेगा विशेष अभियान

रायपुर शहर क्षेत्र के मुख्य अभियंता ने अधिकारियों की ली समीक्षा बैठक

रायपुर । छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बिजली बिल बकाया वसूली के लिए विशेष अभियान चलाएगी। रायपुर (शहर) क्षेत्र के मुख्यअभियंता श्री एम जामुलकर ने मुख्य अभियंता का पद संभालने के लिए बाद अधिकारियों के साथ विद्युत सेवा से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा की।

इस दौरान उन्होंने उपभोक्ता सेवा को प्रमुखता प्रदान करने तथा गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति को पहली प्राथमिकता प्रदान करने अधिकारियों को निर्देश दिए। गुढ़ियारी स्थित क्षेत्रीय मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने बिजली बिल के बकाया वसूली के लिए विशेष अभियान चलाने के भी निर्देश दिए।

बिजली बिल बकाया वसूली के लिए बकाया राशि के अनुरूप अधिकारियों को समीक्षा कर आगामी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि औद्योगिक एवं गैर घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के विरूद्ध बकाया राशि दस हजार तक होने पर कनिष्ठ अभियंता, दस हजार से बीस हजार तक सहायक अभियंता, बीस हजार से पचास हजार तक कार्यपालन अभियंता, पचास हजार से एक लाख तक अधीक्षण अभियंता एवं एक लाख से ऊपर के बकाया राशि पर मुख्य अभियंता समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

बैठक के दौरान रायपुर शहर क्षेत्र के अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता तथा कनिष्ठ अभियंता स्तर के अधिकारी मौजूद थे. इस दौरान श्री जामुलकर ने विभिन्न अधोसंरचना विकास कार्यों की भी समीक्षा की और अपूर्ण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत अधिक से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगाने के लिए प्रेरित करने पर बल दिया। इस दौरान उन्होंने विशेषकर शासकीय सेवकों को इस हेतु आगे आने का आह्वान भी किया। उन्होंने वितरण हानि को कम करने के लिए अधिक कारगर उपायों पर बल दिया। स्मार्ट मीटरिंग को तेजी से पूर्ण करने के लिए सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करने के भी निर्देश दिए।

कलेक्टर गौरव ने सीएमएचओ कार्यालय का किया निरीक्षण

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज रायपुर स्थित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय में उपस्थित रजिस्टर की जांच की और सभी कर्मचारियों को निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को अपने समय की पाबंदी सुनिश्चित करनी होगी ताकि कार्यालय के कार्य बिना किसी रुकावट के चल सकें। उन्होंने यह कदम उठाने के पीछे मुख्य कारण बताया कि इससे आने वाले हितग्राहियों को कोई कठिनाई नहीं होगी और वे आसानी से अपनी सेवाएं ले सकेंगे। इसके अलावा कलेक्टर ने सीएमएचओ कार्यालय के सभी दरवाजों को कार्यकाल के दौरान खुला रखने का आदेश दिया और यह सुनिश्चित करने की बात कही कि कार्यालय के किसी भी गेट पर पर्दा नहीं लगे। उन्होंने कार्यालय के स्टोर रूम के मरम्मत और प्रशिक्षण परिसर में बाथरूम के निर्माण के लिए विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव भेजने के निर्देश भी दिए।

अनुकंपा नियुक्ति पाकर 22 आश्रितों के चेहरे खिले

मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रशासन का जताया आभार

रायपुर। अपने पालक के असामयिक निधन के बाद नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे 22 आश्रितों को आज बिलासपुर नगर निगम में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई। कलेक्टर एवं नगर निगम प्रशासक श्री अवनीश शरण ने मंथन सभागार में सभी आश्रितों को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर निगम कमिश्नर श्री अमित कुमार भी उपस्थित रहे।

गौरतलब है कि 31 दिसंबर 2024 को उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने विभागीय समीक्षा बैठक में निर्देश दिए थे कि सभी नगरीय निकायों में अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रियाएं 10 जनवरी 2025 तक पूरी की जाएं। बिलासपुर नगर निगम ने इन निर्देशों का पालन करते हुए तत्परता से कार्य किया और समय-सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी कर सभी आश्रितों को आज नियुक्ति पत्र प्रदान किए।

नियुक्ति पत्र पाकर आश्रितों के चेहरे खुशी से खिल उठे। सभी ने उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव से मुलाकात की। उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति मिलने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव का आभार जताया। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने आश्रितों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सब मन लगाकर काम करें और संस्थान की प्रगति में योगदान दें।

कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने नगर निगम की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के निर्देशों के अनुरूप प्रक्रिया का क्रियान्वयन किया गया है।

नियुक्ति पाने वालों में श्रीमती नीता ठाकुर, श्रीमती रानो उर्फ क्षमता, श्री वेद प्रकाश, श्रीमती अन्नपूर्णा सोनी, श्री परिवेश परिहार, श्रीमती लक्ष्मी जनोकर, श्रीमती गीता श्रीवास, श्रीमती हसीना बानो, श्री नीलेश श्रीवास, श्री अजीत, श्री मो. यूनूस खान, श्रीमती मीना पाल, श्रीमती बीना, श्री शेख अमीन उल्ला, श्री विनोद कुमार डागोर, श्रीमती मीरा तिवारी, श्रीमती रजनी गुप्ता, श्री प्रदीप बघेल, श्री शेखर मार्को, श्री मो. यूनूस, श्री संजय कुमार, और श्रीमती रेशमा मलिक शामिल हैं।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

भाजपा सरकार के संरक्षण में गौ हत्या हो रही : दीपक बैज

रायपुर। भाजपा सरकार बनने के बाद प्रदेश में गौ तस्करी बढ़ गयी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार के संरक्षण में गौ हत्या हो रही है, गायों की तस्करी हो रही है, गौ मांस की बेधड़क बिक्री हो रही है और आरएसएस के अनुसांगिक संगठन प्रदर्शन का दिखावा कर राजनीतिक पाखंड कर रहे हैं। साय

सरकार की नाकामी से ध्यान भटकाने के लिए बजरंगी सड़कों पर उन्माद फैला रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं। आरएसएस और उनके अनुषांगिक संगठनों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जवाब मांगना चाहिए, निकम्मे गृह मंत्री से इस्तीफा मांगना चाहिए। प्रदेश एवं देश में भाजपा की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में गौ हत्या क्यों हो रहा है? भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रति माह 5000 से अधिक गौ वंश की तस्करी हो रही है। 1 साल के भीतर 60000 से अधिक गौ वंश कत्ल खाना भेजा गया है। जगह-जगह गौ मांस, हड्डी, चमड़ी, ले जाते हुए वाहन पकड़े जा रहे हैं। यह सब भाजपा सरकार की दो विरोधी होने का प्रमाण है। भाजपा की सरकार ने विधानसभा में मंडी कानून में संशोधन करके गौ वंश को प्रदेश के बाहर विदेशों तक पहुंचाने की व्यवस्था कर दी है।

चुनाव जिस भी प्रणाली से हो जीतेगी कांग्रेस ही: शुक्ला

रायपुर। नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से कराये जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ वातावरण है। भाजपा को पता है कि बिना ईवीएम के वह कोई चुनाव नहीं जीत सकती है। पहले स्थानीय निकायों के चुनाव बैलेट पेपर से कराने की घोषणा उसके बाद यू-टर्न लेकर नगरीय

निकायों के चुनाव ईवीएम से कराने का निर्णय बताता है कि भाजपा चुनाव से घबरा रही है। ईवीएम से चुनाव कराने का फैसला भाजपा प्रबंध समिति की बैठक के बाद आया मतलब बैठक में मंथन हुआ कि भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती इसीलिये ईवीएम से चुनाव कराने का निर्णय ले लिया गया। जिन राज्यों में ईवीएम से चुनाव में भाजपा की जीत हुई थी उन्हीं राज्यों में कुछ महिनों के अंदर बैलेट पेपर से हुये स्थानीय निकाय के चुनावों में भाजपा की बुरी तरह पराजय हुई थी। भाजपा यह जान रही है छत्तीसगढ़ में बैलेट पेपर से नगरीय निकाय के चुनाव में भाजपा नहीं जीतने वाली है। इसीलिये घोषणा के बाद भी ईवीएम से चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है जैसे जादूगर की जान तोते में रहती है, वैसे ही भाजपा की जान ईवीएम में बसती है।

सत्ता मिलते महिलाओं से भेदभाव क्यों?: ठाकुर

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि महतारी वंदन योजना से 38000 से अधिक महिलाओं को बाहर करना भाजपा सरकार की महिलाओं के प्रति दुर्भावना है। हर माह महतारी वंदन से जुड़ी महिलाओं की छंटनी की जा रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान सभी महिलाओं को महतारी वंदन योजना से 1000 रु प्रति

महीना देने का वादा किया गया था कोई नियम शर्ते नहीं बताई गई थी। सत्ता मिलने के बाद आखिर महिलाओं में भेदभाव क्यों किया जा रहा है? प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा की आदत है चुनाव को देखते हुए बड़े-बड़े वादा करना और सत्ता मिलते ही वादा खिलाफी करना है। भाजपा को बताना चाहिए महिला के पति अगर सरकारी नौकरी में है? व्यापारी है?इनकम टैक्स भरते हैं? तो इनमें महिलाओं का क्या दोष है? भाजपा ने तो नहीं कहा था कि इन वर्गों के महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वृद्धा पेंशन परित्यक्ता पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं के साथ भी धोखा किया है इनको 1500 रु महीना देना था लेकिन इन्हें सिर्फ हजार रु दिया जा रहा? आखिर भाजपा ने प्रदेश के महिलाओं को धोखा देकर उनका वोट तो प्राप्त कर लिया।

भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त: वर्मा

रायपुर। सुरजपुर में पत्रकार परिवार के ट्रिपल मर्डर की दु:खद घटना की कड़ी नींदा करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में आम जनता हो या पत्रकार कोई भी सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है राजधानी से लेकर ग्रामीण अंचलों तक

हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार और चाकूबाजी का खौफनाक मंजर हर तरफ़ दिखाई दे रहा है। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद अब सूरजपुर से जो खबरें आ रही है वह बेहद डरावनी है। एक पत्रकार के माता-पिता और भाई को कुल्हाड़ी और लाठियां से हमला करके मौत के घाट उतार दिया गया। भाजपा की साय सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को भय मुक्त वातावरण दे पानी में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। इस सरकार में जरा भी नैतिकता बाकी है तो गृह मंत्री स्वयं इस्तीफा दे या विष्णुदेव साय अपराध रोक पाने में नाकाम गृहमंत्री को तत्काल बर्खास्त करें। भाजपा की सरकार में छत्तीसगढ़ का हर शहर अपराध गढ़ बन चुका है। रोज-रोज हत्याएं हो रही है, अपराधी बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं, गैंगवॉर हो रहे हैं, अंतराष्ट्रीय शूटरों की आमद छत्तीसगढ़ में हो गई है।

राज्य युवा महोत्सव 12 से आरू साहू की 'मैं अयोध्या हूँ' से होगा कार्यक्रम का आगाज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 12 जनवरी को खेल संचालनालय परिसर, साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में राज्य युवा महोत्सव का शुभारंभ करेंगे. छत्तीसगढ़ में 3 दिवसीय राज्य युवा महोत्सव का आगाज छत्तीसगढ़ की कलाकार आरू साहू एवं टीम की ''मैं अयोध्या हूँ'' की प्रस्तुति से होगा.

इस महोत्सव में राज्य के युवाओं की प्रतिभा को मंच प्रदान करने के लिए विविध विधाओं में प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा. राज्य युवा महोत्सव के दूसरे दिन सुपर 30 आनंद सर, आरूग बैंड और दायरा बैंड की प्रस्तुति होगी. युवा महोत्सव के अंतिम दिन 14 जनवरी को अनुराग शर्मा के साथ-साथ युवा कवि सम्मेलन में डॉ. कुमार विश्वास एवं उनकी टीम प्रस्तुति देगी. यह महोत्सव छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए अपनी कला, संस्कृति और प्रतिभा को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण मंच होगा.

ओवरब्रिज मरम्मत कार्य में लापरवाही

डिप्टी सीएम ने बीच सड़क पर लगाई अफसरों की क्लास

ईई से पूछा काम करने का मन है या नहीं, नोटिस जारी

रायपुर। डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री ने बीच सड़क पर अफसरों और ठेकेदार की क्लास लगा दी। ओवर ब्रिज की मरम्मत में लापरवाही की शिकायत की जांच करने मौके पर पहुंचे डिप्टी सीएम ने ईई से पूछा कि ऐसे काम करते हैं क्या काम करने का मन है या नहीं। डिप्टी सीएम ने काम करने वाले ठेकेदार का भुगतान रोकने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही मुख्य अभियंता को नोटिस जारी करके तीन दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि यदि ठेकेदार को भुगतान किया गया तो अफसरों के वेतन से काटा जाएगा।

मामला राजधानी रायपुर के मोवा ओवर ब्रिज का है। तीन दिन पहले इस ब्रिज का मरम्मत किया गया था। रातभर मरम्मत के बाद सुबह सड़क को जब यातायता के लिए खोला गया तो उसकी परत उखड़ गई। इसकी जानकारी मिलते ही डिप्टी सीएम अरुण साव विभागीय सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह के साथ मौके पर पहुंच गए। मरम्मत में लापरवाही देखकर भड़के डिप्टी सीएम ने पहले ठेकेदार की क्लस लगाई। पूछा काम करना आता है या नहीं। इसके बाद उन्होंने मौके पर मौजूद

ईई की क्लास ली। पूछा कि काम करना आता है या नहीं। काम होता है तो कुछ देखते हैं। ऐसे ही काम कराते हैं, काम करने का मन नही है।

रायपुर के मोवा ओवरब्रिज मरम्मत कार्य में लापरवाही की खबर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज मौके पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्य स्थल में सड़क मरम्मत कार्य लापरवाही पूर्वक एवं गुणवत्ताविहीन पाया गया। मौके पर संबंधित ठेकेदार और इंजीनियर्स को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि, यह सुशासन की सरकार है, इसमें अनियमिता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक रुपए का भी भुगतान नहीं होगा ठेकेदार को, जब तक गुणवत्ता पूर्ण कार्य नहीं हो जाता, भुगतान करने पर अधिकारियों की सैलरी से कटेंगे पैसे।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने उच्च अधिकारियों को मौके पर निर्देशित किया कि, मुख्य अभियंता स्तर अधिकारी के नेतृत्व में ओवरब्रिज मरम्मत कार्य की जांच कर तीन दिन में रिपोर्ट पेश करें। श्री साव ने सख्त लहजे में कहा कि, गुणवत्ताविहीन कार्य के लिए जिम्मेदार अधिकारी नहीं बख्शेंगे, जांच के बाद कड़ी कार्रवाई होगी। बता दें कि, औचक निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।उप मुख्यमंत्री अरुण साव के सख्त निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश में लिखा है कि 10 जनवरी को उप मुख्यमंत्री ने मोवा ओव्हरब्रिज का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान कार्य स्थल पर खराबी पाई गई।

सीएम साय की निर्देशों का त्वरित अमल

समय पर नहीं पहुंचने पर होगी कड़ी कार्रवाई

रायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशों का अब त्वरित अमल हो रहा है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में कलेक्ट्रेट के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समस्याओं को सुना। कलेक्टर डॉ. सिंह ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दोपहिया वाहन चलाने के दौरान हेलमेट लगाने एवं कार सवार को शीटबेल्ट लगाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि विभागीय प्रमुख निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचे और कर्मचारियों के भी समय पर निर्धारित समय पर पहुंचना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने सभी विभागों के उपस्थिति रजिस्टर की

जांच की और उपस्थिति की जांच की। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि अब समय पर कार्यालय नहीं पहुंचने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि कलेक्ट्रेट में पहुंचने वाले सभी आमजनों के साथ अधिकारी एवं कर्मचारी सहज व्यवहार रखें और कार्यालयों की साफ-सफाई भी रखी जाएं। कलेक्टर ने कहा कि महिला एवं पुरूष टॉयलेट की सफाई समय-समय पर की जाएं।

कलेक्टर डॉ. सिंह ने कहा कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 5:15 बजे सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच की जाएगी। अनुपस्थित मिलने पर संबंधित पर कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही प्रत्येक कार्यालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम की पट्टिकाएं होना अनिवार्य है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.